सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

राजधानी चौपाल
समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...
94169-26329
93068-13001

अंक : 13 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (01 से 07 अप्रैल 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

डिजिटल और बारूद की जंग : ईरान का 'अमेजन' पर प्रहार, ट्रंप का दो सप्ताह का अल्टीमेटम

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | अभी तक युद्ध का मतलब सीमाओं पर टैंकों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की भिड़ंत माना जाता था, लेकिन बुधवार को ईरान ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। तेहरान ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी अमेजन के बहरीन स्थित डेटा सेंटर पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर यह साफ कर दिया है कि अब लड़ाई 'जमीन' से ज्यादा 'सर्वर' पर लड़ी जाएगी। 'राजधानी चौपाल' की यह विशेष रिपोर्ट उन तमाम कड़ियों को जोड़ती है, जो इस समय दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर चुकी हैं।

ट्रंप का 'दो सप्ताह' का दांव और नाटो से तौबा

वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति से दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष को एक से दो सप्ताह में खत्म कर सकते हैं। लेकिन उनका तरीका बेहद सख्त है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका, होर्मुज जलमार्ग को खुलवाने का ठेका नहीं लेगा। "जो देश इस पर निर्भर हैं, जिम्मेदारी उनकी है," ट्रंप के इस बयान ने सहयागी देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सबसे बड़ी हलचल नाटो गठबंधन में मची है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय देश इस संकट में अमेरिका का साथ नहीं देते, तो अमेरिका इस पुराने सैन्य गठबंधन से अलग हो सकता है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की चूलें हिला देने वाला है।

बहरीन के आसमान में बुधवार को जब ईरानी मिसाइलें और ड्रोन फटे, तो उसका सीधा असर दुनिया भर के क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क पर पड़ा। अमेजन वेब सर्विस का यह डेटा सेंटर मध्य पूर्व में कंपनी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। हमले के बाद सेंटर में लगी भीषण आग ने न केवल करोड़ों डॉलर का नुकसान किया, बल्कि वैश्विक डेटा सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए।

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनके निशाने पर अब माइक्रोसॉफ्ट, एपल, गूगल और मेटा जैसी 18 दिग्गज अमेरिकी कंपनियां हैं। यह पहली बार है जब किसी देश ने औपचारिक रूप से निजी टेक कंपनियों को सैन्य निशाना बनाने की घोषणा की है।

होर्मुज की घेराबंदीः तेल और व्यापार का दम घुटने लगा : रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान ने पूर्ण नियंत्रण का दावा कर दिया है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए ईरान ने कतर की ऊर्जा कंपनी द्वारा लीज पर लिए गए एक विशाल टैंकर पर तीन क्रूज मिसाइलें दागीं। हालांकि, चालक दल के 21 सदस्य बाल-बाल बच गए, लेकिन इस एक हमले ने वैश्विक समुद्री व्यापार की कमर तोड़ दी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही 70% तक गिर गई है। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूते हुए 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुँची हैं। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो दुनिया को 1970 के दशक जैसे तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

फेंटानिल और बारूदः युद्ध का 'नशीला' मोड़ : युद्ध के मैदान में अब रसायनों का खेल भी शुरू हो गया है। इजरायली वायुसेना ने ईरान की उस फैक्ट्री को खंडहर में तब्दील कर दिया, जहां 'फेंटानिल' बनाई जाती थी। अमेरिका और इजरायल का आरोप है कि ईरान इस रसायण का इस्तेमाल अपने गोला-बारूद में 'केमिकल वेपन' के तौर पर कर रहा है। वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे 'अस्पतालों पर हमला' करार दिया है। उनके अनुसार, यह फैक्ट्री केवल दर्द निवारक दवाएं बनाती थी। 'एक्स' पर साझा की गई फैक्ट्री की तस्वीरें अब अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई हैं। क्या यह वास्तव में दवा थी या मौत का सामान? यह जांच का विषय है, लेकिन बमबारी ने तनाव को चरम पर पहुँचा दिया है। जहाँ एक तरफ अमेरिका और इजरायल एक सुर में हैं, वहीं ब्रिटेन ने अपनी राह अलग कर ली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दो-टूक कहा है कि "यह हमारा युद्ध नहीं है।" ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका के सैन्य अभियानों में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन ने होर्मुज संकट पर अलग से 35 देशों की बैठक बुलाकर यह संदेश दिया है कि वह इस मुद्दे का समाधान कूटनीति से चाहता है, न कि मिसाइलों से।

ईरान-अमेरिका जंग के बीच मोदी सरकार ने लिए राहत के दो फैसले

न लगेगा लॉकडाउन, न महंगा होगा तेल; अफवाहों के बाजार पर लगाम

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | पश्चिम एशिया में संघर्ष से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल है। कच्चा तेल 122 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुका है, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 10 प्रति लीटर की कटौती की है। अब पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 प्रति लीटर से घटाकर 23 प्रति लीटर हो गया। डीजल पर 10 प्रति लीटर से घटकर 0 हो गया। इसके साथ ही, सरकार ने लॉकडाउन की अफवाहों को भी सिरे से खारिज किया है।

कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाकर 70 प्रतिशत की

- **नया रूटः** भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित होने के बाद सप्लाई चेन बदली है। अब वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से कच्चा तेल मंगाया जा रहा है।
- **गैस सप्लाईः** देश में गैस की किल्लत न हो, इसके लिए पेट्रो केमिकल उत्पादन से गैस को एलपीजी उत्पादन की ओर डायवर्ट किया है। एलपीजी के लिए रूस, ऑस्ट्रेलिया से नए अनुबंध किए गए हैं।
- **कमर्शियल राहतः** होटलों और उद्योगों के लिए कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति 50% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है।
- **सख्त कार्रवाईः** 3,000 से अधिक छापेमारी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 26 और डीजल पर 81.90 प्रति लीटर घाटा हो रहा था। दैनिक घाटा 2,400 करोड़ तक हो गया था। एक्साइज में कटौती उन कीमतों को 'ऑफसेट' (बराबर) करेगी, जो युद्ध से बढ़नी तय थीं। हालांकि सरकारी खजाने को सालाना करीब 1.75 लाख करोड़ का नुकसान होगा। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा, हर पंद्रह दिन में डीजल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की समीक्षा होगी। देश में उपलब्धता के लिए डीजल निर्यात पर 21.5 प्रति लीटर और एटीएफ निर्यात पर 29.5 प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगाया गया है।

मोदी का मुख्यमंत्रियों को मंत्र - एकजुट रहें : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने कहा, युद्ध के कारण स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा और जनहित की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा, जैसे कोविड महामारी के दौरान केंद्र और राज्यों ने 'टीम इंडिया' बनकर काम किया था, वैसी ही एकजुटता इस ऊर्जा संकट में भी दिखानी होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह रोज स्थिति की समीक्षा कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लिए जा सकें।

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा- लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, 'लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेताओं व अन्य लोगों को अफवाह फैलाने और डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर न पड़े। वहीं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, क्रूड की तेजी से कंपनियों पर दबाव था, सरकार ने राहत दी।

प्रदेश में 1 अप्रैल से नए कलेक्टर दरों में 75 फीसदी तक की हुई बढ़ोतरी

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा में आज से नए कलेक्टर रेट्स लागू होंगे। इनको बाजार मूल्य के अनुरूप अपडेट किया गया है। इस बार का संशोधन पूरी तरह डेटा-आधारित और तर्कसंगत फॉर्मूले पर आधारित है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र (सेगमेंट) की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है, जहां लेन-देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक पाई गई।

सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुसार, कलेक्टर रेट में वृद्धि को विभिन्न स्लैब्स में विभाजित किया गया है। जिन क्षेत्रों में लेन-देन मूल्य कलेक्टर रेट से 0 से 20 प्रतिशत तक अधिक था, वहां कोई वृद्धि नहीं की गई। 20 से 35 प्रतिशत वाले सेगमेंट में 15 प्रतिशत, 35 से 70 प्रतिशत में 25 प्रतिशत, 70 से 100 प्रतिशत में 30 प्रतिशत, 100 से 150 प्रतिशत में 45 प्रतिशत, 150 से 200 प्रतिशत में 60 प्रतिशत व 200 प्रतिशत से अधिक वाले मामलों में अधिकतम 75 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।

राज्य में कुल 1,60,752 सेगमेंट्स का विश्लेषण किया गया। इनमें से 68.80 प्रतिशत (1,10,607 सेगमेंट) ऐसे रहे, जहां 0 से 20 प्रतिशत श्रेणी में आने के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई। 5.72% (9,203 सेगमेंट) में 15%, 7.82% (12,585 सेगमेंट) में 25%, 4.03% (6,492 सेगमेंट) में 30%, 4.01 % (6,451 सेगमेंट) में 45%, 2.15% (3,467 सेगमेंट) में 60% व 7.43% (11,947 सेगमेंट) में 75% की वृद्धि लागू की गई।

सरकार का दावा है कि यह मॉडल पूरी तरह पारदर्शी, संतुलित और जनहित में तैयार किया गया है, इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े और बाजार के वास्तविक मूल्य के अनुसार रेट निर्धारित हो सकें।

वरिष्ठ न्यायिक सेवा भर्ती में अब 65 के बजाय 50 अंक की होगी लिखित परीक्षा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार न्यायिक सेवा में अब भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा 65 के बजाय 50 अंक की होगी। इसके अलावा 25 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके लिए परीक्षा भी होगी। यदि इन 25 प्रतिशत पदों पर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे या परीक्षा के लिए निर्धारित अंक लाने वाले नहीं मिलते हैं तो फिर ये पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। 25 प्रतिशत पद हाई कोर्ट द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भरे जाएंगे।

यदि किसी अधिवक्ता ने न्यायिक सेवा से पहले ही बार में सात वर्ष पूरे कर लिए हैं तो वह वरिष्ठ न्यायिक सेवा की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का हकदार होगा। यदि न्यायिक सेवा में भी सात वर्ष का अनुभव हासिल कर लिया है तो वह भी वरिष्ठ न्यायिक सेवा में शामिल हो सकेगा। इसके अलावा यहां पर पदों को रोस्टर के अनुसार भरा जाएगा।

₹1.80 लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे ही निजी स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चिराग योजना के पात्रता नियमों पर बड़ा यू-टर्न लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में दाखिले के पात्र नहीं होंगे।

30 मार्च तक देनी थी जानकारी

अभिभावकों को स्कूलों का चयन 30 मार्च तक किया जाना था। इसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूलों का चयन कर लिया था, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब इसे अचानक 1.80 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे परिवारों के बच्चों के अरमान अब पूरे नहीं हो पाएंगे। यानी इनको या तो खुद फीस देनी होगी या सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने 2 माह पहले लिए फैसले को पलटते हुए आय की सीमा को दोबारा घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया है। इस बदलाव से उन हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों के अरमान टूट गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखा था।

शिक्षा विभाग के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि पहले दिए गए आदेश वापस लिए जाते हैं। अब केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में 1.80 लाख रुपए या उससे कम सत्यापित है। बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को जारी निर्देशों में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया था। अब विभाग का कहना है कि पहले 8 लाख आय वाला पत्र गलती से जारी हो गया था।

सात समंदर पार की जंग, आपके घर में महंगाई की दस्तक; मध्यम वर्ग का बजट हुआ ध्वस्त

हिसार/नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में छिड़ी मिसाइलों की जंग अब केवल सरहदों तक सीमित नहीं रही है। ईरान द्वारा अमेरिकी टेक दिग्गज 'अमेजन' के डेटा सेंटर पर किए गए हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जे के दावों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ऐसा कंपन पैदा किया है, जिसकी सीधी आंच भारत के आम घरों तक पहुँच गई है।

यह युद्ध अब आपके फ्रिज, एसी, दूध की थैली और यहाँ तक कि रोजमर्रा के नमक-तेल पर हुआ एक सीधा आर्थिक प्रहार बन चुका है। 'राजधानी चौपाल' की पड़ताल बताती है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने न केवल माल ढुलाई को महंगा किया है, बल्कि उन तमाम उत्पादों की लागत बढ़ा दी है जो हमारी सुबह से शाम तक की जरूरतों का हिस्सा हैं।

प्लास्टिक उद्योग पर प्रहारः 20 हजार इकाइयों में लटका ताला

इस वैश्विक तनाव का सबसे घातक असर देश के सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र, विशेषकर प्लास्टिक सेक्टर पर पड़ा है। प्लास्टिक आज के दौर में हर उत्पाद की पैकेजिंग की जान है, लेकिन कच्चे तेल से बनने वाले पॉलीमर और एलडीपीई दाने की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि देश भर की लगभग 50 हजार प्लास्टिक फैक्ट्रियों में से 20 हजार से ज्यादा इकाइयां बंद होने की कगार पर पहुँच चुकी हैं। राजकोट, हैदराबाद और मध्य प्रदेश जैसे औद्योगिक केंद्रों में सन्नाटा है, क्योंकि उद्यमियों को न तो किफायती कच्चा माल मिल रहा है और न ही उत्पादन के लिए जरूरी कमर्शियल एलपीजी।

महंगी हुई ठंडी हवाः एसी और फ्रिज के दामों में भारी उछाल

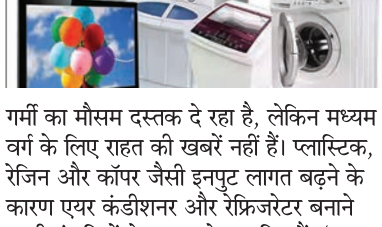

गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए राहत की खबरें नहीं हैं। प्लास्टिक, रेजिन और कॉपर जैसी इनपुट लागत बढ़ने के कारण एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 'ब्लू स्टार' और 'हेयर' जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में 15 प्रतिशत तक का इजाफा कर दिया है।

कंपनियों का कहना है कि वे लंबे समय तक बढ़ती लागत का बोझ खुद नहीं उठा सकतीं। यदि कच्चे माल की किल्लत और समुद्री मार्ग का संकट इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले दिनों में कीमतों में 3-4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होना तय है।

किराना और रोजमर्रा के सामान पर 'महंगाई का डाका'

युद्ध की यह आंच अब आपके रसोई के राशन तक भी पहुँच गई है। चूंकि अधिकांश एफएमसीजी उत्पाद जैसे बिस्किट, नमकीन, दूध और तेल प्लास्टिक की पैकिंग में आते हैं, इसलिए पैकेजिंग सामग्री महंगी होने से इन उत्पादों की कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। बोतलबंद पानी की लागत में ही एक रुपये प्रति बोतल का इजाफा हो चुका है। 'पारले प्रोडक्ट्स' और 'आर्कियन फूड्स' जैसी कंपनियां फिलहाल स्थिति का आकलन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुनाफा कम होने की स्थिति में वे जल्द ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए यह बोझ आम ग्राहकों पर डाल देंगी।

बदलती जीवनशैलीः 'रेडी-टू-ईट' और इंडक्शन का बढ़ता क्रेज

कमर्शियल गैस की किल्लत और प्रवासी कामगारों के पलायन ने शहरी परिवारों के खाना पकाने के तरीके को भी बदल दिया है। गैस की ऊंची कीमतों और उपलब्धता की कमी के कारण लोग अब 'रेडी-टू-ईट' यानी झटपट बनने वाले भोजन की ओर रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स की मांग में भारी उछाल आया है। इतना ही नहीं, गैस के विकल्प के रूप में बिजली से चलने वाले इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री भी सामान्य से 10 गुना तक बढ़ गई है। लोग अब पारंपरिक चूल्हे के बजाय तकनीक का सहारा लेकर महंगाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

निर्माण क्षेत्र की चुनौतीः सीमेंट और पेटकोक का संकट

भारी उद्योग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल से अछूते नहीं हैं। सीमेंट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले पेटकोक और बोरियों के लिए जरूरी प्लास्टिक की कीमतें बढ़ने से उत्पादन लागत में प्रति टन 200 रुपये तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि बाजार की सुस्ती के कारण कंपनियों को बढ़ी हुई कीमतें कुछ जगहों पर वापस लेनी पड़ी हैं, लेकिन उत्तर भारत के बाजारों में 10 से 15 रुपये प्रति बोरी की तेजी अब भी बनी हुई है। कुल मिलाकर, यह युद्ध एक ऐसी आर्थिक जंजीर बन गया है जिसने समाज के हर वर्ग को अपनी चपेट में ले लिया है।

एक अप्रैल से नई दरें लागू, सर्किल रेट में 15 से 75 फीसदी तक बढ़ोतरी पर मुहर

मिलेनियम सिटी में बढ़े हुए सर्किल रेट पर रजिस्ट्री होंगी, टोल से गुजरना भी हुआ महंगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मिलेनियम सिटी में बुधवार से बढ़े हुए सर्किल रेट (कलेक्टर रेट) पर जमीन की रजिस्ट्री होंगी। सर्किल रेट में 15 फीसदी से 75 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। इस बीच मंगलवार रात 12 बजे के बाद से टोल की दरें लागू हो गईं। टोल दरों में पांच से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

जिले में एक अप्रैल से सदर बाजार, बजघेड़ा और भूतेश्वर मंदिर क्षेत्र के इलाके की जमीन महंगी हो जाएगी। नई दरों में 15 से 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसमें सबसे अधिक रेट द्वारका एक्सप्रेसवे के बजघेड़ा गांव में बढ़ाए गए हैं। यहां कृषि भूमि और कॉमर्शियल के रेट में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नया रेट लागू होने पर यहां की कृषि भूमि का रेट 7 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई।

राजस्व विभाग के अनुसार बजघेड़ा में एक एकड़ जमीन का सर्किल रेट 4 करोड़ 30 लाख 30 हजार रुपये है। नया रेट लागू होने पर यहां की कृषि भूमि का रेट 7 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपये प्रति एकड़ किया गया है। सराय अलावर्दी में भी कृषि भूमि का रेट 75 फीसदी बढ़ाया गया है। सुखराली में भी आवासीय जमीन के रेट में 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। गोपाल नगर, अशोक विहार, सदर बाजार से भूतेश्वर मंदिर तक के क्षेत्र की दुकानों और ऑफिस के लिए कॉमर्शियल रेट में भी 75 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे व्यापारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी और स्टांप ड्यूटी का बोझ भी बढ़ेगा। न्यू कॉलोनी क्षेत्र में व्यावसायिक दरों में 45 फीसदी और आवासीय में 25 फीसदी वृद्धि है। सिविल लाइंस से जेल सड़क की व्यावसायिक प्रॉपर्टी में भी वृद्धि की गई है। कार्टरपुरी क्षेत्र की आवासीय दरों में 60 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

कलेक्टर रेट को लेकर 47 सुझाव आए : कलेक्टर रेट को लेकर लोगों के आए 47 सुझाव को लेकर मंगलवार देर शाम सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय पर डीसी अजय कुमार के साथ जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलों की बैठक हुई। सभी तहसील क्षेत्र के कलेक्टर रेट में संशोधन हुए। जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव ने कहा कि कलेक्टर रेट 15 से 75 प्रतिशत तक रहेगा। कुछ गांवों के कलेक्टर रेट 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। इसमें मामूली संशोधन किया गया है। बाकी शहरी क्षेत्र के कनेक्टर रेट में बदलाव नहीं हुए हैं। नए कनेक्टर रेट के अनुसार तहसील-उप तहसील में जमीनों की रजिस्ट्री होगी।

द्वारका एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर महंगा

द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद सफर महंगा हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल पर कार वालों को एक तरफ के सफर के लिए 225 रुपये चुकाना पड़ा। पहले के मुकाबले पांच रुपये ज्यादा है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे के घामडौज टोल प्लाजा पर भी अब कार और जीप के लिए 125 की जगह 130 रुपये टोल देना पड़ रहा है। एनएचएआई के मुताबिक टोल दरों में यह बदलाव सालाना समीक्षा पर किया गया है।

▪ **सीएनजी सस्ती होने के आसार :** हरियाणा सिटी गैस कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सीएनजी में वैट दर घटाने का आदेश आता है तो कंपनी की बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी। सीएनजी दर कम करने का फैसला लिया जाएगा। अभी गुरुग्राम में सीएनजी 86.50 रुपये प्रति किलो है। प्रतिदिन सात लाख किलोग्राम सीएनजी की खपत वाहनों में हो रही है।

न्यूज ब्रीफ

एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए गैस सिलेंडरों की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम शुरू

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने और शिकायतों के लिए लघु सचिवालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सातों दिन और 24 घंटे कंट्रोल रूम के नंबर 0124-2868930 पर शिकायत की जा सकेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को की गई। शिकायत पर तत्काल विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। डीसी अजय कुमार ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाते हुए लघु सचिवालय के सेकेंड फ्लोर स्थित एनआईसी रूम में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां आमजन गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता, आपूर्ति में देरी, कालाबाजारी या अवैध भंडारण जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डीएफएससी डॉ. अशोक रावत ने बताया कि कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जाएगा। लोगों से अपील की गई कि यदि कहीं भी एलपीजी से जुड़ी कोई अनियमितता नजर आए तो तुरंत कंट्रोल रूम में सूचित करें।

ई-बस डिपो निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा, नीचे ई-बस डिपो और ऊपर शॉपिंग मॉल बनेगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सेक्टर-65 में ई-बस डिपो के लिए करीब डेढ़ एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले तीन से चार महीने के अंदर बस डिपो निर्माण के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को जमीन मिलने की उम्मीद है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-65 में 220केवीए बिजली घर बनाने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को जमीन दी थी। यह बिजली घर छह एकड़ जमीन में तैयार हो गया। छह एकड़ जमीन को एचवीपीएन ने एचएसवीपी के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद जीएमडीए ने 60 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित इस जमीन का चयन ई-बस डिपो के निर्माण के लिए किया।

एचएसवीपी की तरफ से ई-बस डिपो के लिए यह जमीन देने से इंकार किया था। इसके पीछे तर्क दिया था कि यह जमीन पर मार्केट विकसित की जा सकती है, जिससे 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि मिल सकती है। बाद में फैसला हुआ कि इस जमीन पर नीचे ई-बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। इसके ऊपर शॉपिंग मॉल तैयार करके दुकानों को बेचा जा सकता है।

बाइक फिसलने से गिरा इनामी बदमाश गिरफ्तार

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गोल्फ कोर्स रोड स्थित डीएलएफ फेज-1 के एक मकान पर गोली चलाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक पांच हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर जब भागने लगा तो बाइक फिसलने से नीचे गिर गया। इस दौरान उसका पैर टूट गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। अपराध शाखा सेक्टर-40 के मुताबिक सोनीपत के गांव सरधाना निवासी 30 वर्षीय प्रवीण उर्फ पिन्ना पर हत्या और शस्त्र अधिनियम के दो मामले पानीपत में और एक मामला दिल्ली में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रवीण ने अपने साथी मोहित के साथ मिलकर डीएलएफ फेज-1 की इमारत पर गोली चलाने के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे। मामले में अब तक गुरुग्राम पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवीण के कब्जे से दो पिस्टल, 41 कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से मामले की पूछताछ की जा रही।

खेल नर्सरी के मैदानों में एक बार फिर रौनक लौटी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| अप्रैल के साथ ही जिले में खेल गतिविधियों की नई शुरुआत हो गई है। जिला खेल विभाग के तहत संचालित खेल नर्सरियों की शुरुआत बुधवार से कर दी गई। फिलहाल पहले चरण में सरकारी मैदानों में चलने वाले खेल केंद्रों को शुरू किया गया है, जबकि अन्य केंद्रों की सूची निदेशालय की ओर से आना अभी बाकी है। इसके बाद ही प्राइवेट सेंटरों को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ताऊ देवीलाल, भंगरोला, नेहरू स्टेडियम समेत कई स्थानों पर खिलाड़ियों ने पहुंचकर नियमित प्रशिक्षण की शुरुआत की। जिला खेल विभाग के तहत संचालित करीब 21 खेल प्रशिक्षकों ने अपने-अपने खेलों में नर्सरियों का संचालन शुरू किया। ट्रायल के आधार पर चयनित खिलाड़ियों ने पहले दिन से ही अभ्यास की जिम्मेदारी संभाल ली। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो समेत विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। मैदानों में एक बार फिर रौनक लौटती नजर आई। जिला खेल अधिकारी आरती सोलंकी ने बताया कि खिलाड़ियों को तय समय अवधि तक नियमित अभ्यास करना होगा, जिसमें उपस्थिति और प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के आधार पर आगे चलकर खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप की राशि भी प्रदान की जाएगी।

सिकंदरपुर में दो करोड़ की लागत से नाला बनेगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मानेसर नगर निगम की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने बुधवार को गांव सिकंदरपुर में दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे बरसाती नाले का शिलान्यास किया। इसके बनने से गांव में जलभराव की पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर वार्ड 19 के पार्षद रवि यादव, निगम अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। मेयर ने अपने संबोधन में कहा कि निगम क्षेत्र के सभी गांवों का बिना भेदभाव समान विकास किया जाएगा और हर गांव में माइक्रो एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जल प्रदूषण पर अंकुश लग सके। सेक्टर-83, 84 और 85 के लिए एक नया कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। सेक्टर-83 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेक व्यू पार्क और मंदिर का निर्माण होगा। मेयर ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम क्षेत्र के हरसरू, नैनवाल और सेक्टर-6 में मलबे के लिए तीन डंपिंग साइट बनाई जाएंगी।

फीस : 10 से 15% तक बढ़ने से अभिभावकों की चिंता बढ़ी

निजी स्कूलों की किताबें, कॉपी 30% महंगी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग भी महंगे

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शहर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर महंगाई का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस बार किताबों और कॉपियों की कीमतों में करीब 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते-जुराब और अन्य जरूरी सामान भी 10 से 20 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। इससे परिवारों का बजट गड़बड़ा गया है। शहर के कई निजी स्कूलों में एक ही जगह से कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि पिछले साल जहां एक बच्चे का पूरा सेट 6 से 8 हजार रुपये में आ जाता था, वहीं इस बार यही खर्च बढ़कर 10 से 15 हजार रुपये तक पहुंच गया है।

यूनिफॉर्म की कीमतों में भी 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। शर्ट, पैंट, स्कर्ट, जूते और टाई-बेल्ट जैसे जरूरी सामान अलग-अलग महंगे हो गए हैं। वहीं किताबों और कॉपियों के पैकेज भी पहले के मुकाबले काफी महंगे मिल रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पहले जहां दूसरी कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम करीब 5000 रुपये में मिल जाता था, वहीं इस बार इसकी कीमत बढ़कर 6500 से 6800 रुपये तक पहुंच गई है। चौथी कक्षा का कोर्स भी 6000 रुपये से बढ़कर करीब 7200 रुपये हो गया है।

ऐसे में एक बच्चे पर ही हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि स्कूल बैग की कीमत भी 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। यूनिफॉर्म, जूते, कॉपियां और स्टेशनरी के दाम बढ़ने से कुल खर्च में भारी इजाफा हुआ है। जिन परिवारों में दो या अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए यह खर्च और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है।

वहीं, फरीदाबाद में भी यहीं स्थिति है। पाठ्यक्रम के साथ स्कूल बैग, वर्दी, जूते-जुराब, पानी की बोतल सहित अन्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इन सब में भी 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। निजी स्कूलों के समीप स्थित पाठ्य पुस्तकों की दुकान पर अभिभावकों की भीड़ देखी जा सकती है। पिछले वर्ष तक दूसरी कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम करीब 5000 रुपये में मिल जाता था, जो इस बार बढ़कर 6500 से 6800 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह चौथी कक्षा का पाठ्यक्रम भी 6000 रुपये से बढ़कर 7200 रुपये हो गया है। इससे बजट बिगड़ गया है।

स्कूलों में 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत

गुरुग्राम|नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत बुधवार से हो रही है। इसी के साथ जिले के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, प्रगति और स्कूल की व्यवस्थाओं से अवगत कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बार सत्र की शुरुआत को संवाद, पारदर्शिता और डिजिटल जुड़ाव पर केंद्रित किया है, ताकि अभिभावकों की भागीदारी बढ़े और बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। पहले ही दिन अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार, उपस्थिति, यूनिफॉर्म, किताबों और समय सारिणी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार इस बार पीटीएम की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला, खंड और क्लस्टर स्तर के अधिकारी अलग-अलग स्कूलों का दौरा करेंगे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे।

अधिकारी न केवल कार्यक्रम की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे, बल्कि अभिभावकों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी जुटाएंगे। विभाग का उद्देश्य है कि हर स्कूल में होने वाली गतिविधियां पारदर्शी और प्रभावी रहें तथा अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। पीटीएम के बाद प्रत्येक विद्यालय के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। स्कूल प्रमुखों को गूगल फॉर्म के माध्यम से पूरी जानकारी भरनी होगी, जिसे निपुण हरियाणा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इसके तहत पहले स्कूल स्तर पर रिपोर्ट तैयार होगी, फिर क्लस्टर प्रमुख के माध्यम से इसे ब्लॉक कार्यालय भेजा जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया से राज्य स्तर पर पूरे कार्यक्रम की निगरानी संभव हो सकेगी और प्रत्येक विद्यालय के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इस सत्र में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा।

एलपीजी की कमी से स्टील-सीमेंट के उत्पादन पर असर, गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| एलपीजी की आपूर्ति में कमी से रिफ्रैक्टरी उद्योग पर संकट मंडराने लगा है। इससे जुड़े स्टील, सीमेंट और कांच के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है।

रिफ्रैक्टरी उद्योग उन ईंटों और सामग्रियों का निर्माण करता है, जिनका इस्तेमाल स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री और एल्युमीनियम भट्टियों में किया जाता है। इन भट्टियों का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। इस तापमान को बनाए रखने के लिए एलपीजी सबसे स्वच्छ और प्रभावी ईंधन माना जाता है। पिछले कुछ समय से इसकी आपूर्ति बाधित होने के कारण रिफ्रैक्टरी बनाने वाली फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा या बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी प्रमोद सागर ने कहा कि यह केवल एक फैक्ट्री की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए जोखिम है। ईंधन की अस्थिरता के कारण उत्पादन की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि औद्योगिक सप्लाई चेन न टूटे। उद्यमियों का कहना है कि उद्योग को अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर बदलना आसान नहीं है। रिफ्रैक्टरी भट्टियों का डिजाइन जटिल होता है। इन्हें विशेष रूप से गैस या एलपीजी के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे ईंधन पर जाने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है।

शहर में 35% रेहड़ियां बंद : शहर में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण 35 प्रतिशत छोटे ढाबे और रेहड़ी-पटरी के खाने-पीने के स्टॉल बंद हो गए हैं, जबकि कई बंद होने की कगार पर हैं।

सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग

इंडियन रिफ्रैक्टरी मेकर्स एसोसिएशन (आईआरएमए) ने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। आईआरएमए की चेयरमैन सुनंदा सेनगुप्ता ने स्पष्ट किया कि रिफ्रैक्टरी उद्योग स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों को चलाने में मदद करता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जिस तरह घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की प्राथमिकता दी जाती है, उसी तरह रिफ्रैक्टरी उद्योग को भी निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भारत के बड़े स्टील प्लांट रिफ्रैक्टरी की नियमित सप्लाई पर निर्भर हैं। यदि सप्लाई रुकी तो स्टील और निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। रिफ्रैक्टरी भट्टियां खास तौर पर गैस और एलपीजी के लिए डिजाइन की जाती हैं। अचानक किसी दूसरे ईंधन पर शिफ्ट होना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव नहीं है। ईंधन की कमी से अब कनवर्टर ब्रिक्स जैसी जरूरी चीजों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

अनाज मंडी में एक माह बाद फिर अटल रसोई शुरू

सोहना (राजधानी चौपाल)| अनाज मंडी में रबी की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को एक राहत दी गई है। मंडी परिसर में पिछले करीब एक महीने से बंद पड़ी अटल रसोई को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के साथ ही मार्केट कमेटी प्रशासन ने इस रसोई को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। मंडी में फसल की बिक्री और तोल के दौरान कई बार किसानों को अपनी बारी का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में यह अटल रसोई उनके लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी।

'ब्रैडीकार्डिया' के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच अब ब्रैडीकार्डिया जैसी खामोश लेकिन गंभीर समस्या भी तेजी से चिंता का विषय बनती जा रही है। गुरुग्राम स्थित मेदांता द मेडिसिटी में आयोजित एक वर्कशॉप में कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों ने इस बीमारी की समय पर पहचान और इलाज को लेकर गंभीर चेतावनी दी। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रैडीकार्डिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आराम की अवस्था में हृदय की धड़कन 60 बीट प्रति मिनट से कम हो जाती है। यह बीमारी हर एक हजार में से लगभग एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्रैडीकार्डिया के लक्षण अक्सर इतने सामान्य होते हैं कि मरीज उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार थकान, चक्कर आना, सांस फूलना, कमजोरी, व्यायाम करने में परेशानी और कभी-कभी बेहोशी जैसे संकेत इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं।

हयातपुर में निरमाया प्रोजेक्ट का जागरूकता कार्यक्रमः 17 टीबी मरीजों को मिली पोषण किट, "टीबी मुक्त भारत" का लिया संकल्प

गुरुग्राम/हयातपुर (राजधानी चौपाल)| हयातपुर स्थित सामुदायिक केंद्र में 30 मार्च को निरमाया प्रोजेक्ट, गुरुग्राम द्वारा एक व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता एवं प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 83 लोगों ने भाग लिया और "टीबी मुक्त भारत" के लक्ष्य को लेकर सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पोषण विशेषज्ञ सुश्री वैष्णवी के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद एनएचक्यू से आए श्री चंदन वर्मा ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को गमले भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया (एचपीपीआई) के कार्यों का परिचय देते हुए बताया कि निरमाया परियोजना गुरुग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्य अतिथि चरण सिंह यादव (समाजसेवी, हयातपुर) ने एचपीपीआई के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने संगठन को धन्यवाद दिया और भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने 17 टीबी मरीजों को छह माह के लिए पोषण किट वितरित की।

विशिष्ट अतिथियों में डॉ. परवीन (गढ़ी पीएचसी) और डॉ. संदीप (कासन पीएचसी) ने अपने-अपने क्षेत्रों में एचपीपीआई द्वारा किए जा रहे कार्यों—जैसे आशा और एएनएम प्रशिक्षण, सर्वाइकल कैंसर जागरूकता, वीआईए परीक्षण, टीबी स्क्रीनिंग, पोषण किट वितरण तथा मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच—की सराहना की। उन्होंने भविष्य में भी इस सहयोग को जारी रखने की इच्छा जताई।

डीटीओ कार्यालय से आईं सुश्री पूनम (पीपीओ) ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए विभाग और एचपीपीआई मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने टीबी स्क्रीनिंग, एक्स-रे सहायता, बलगम जांच और पोषण किट वितरण जैसे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों को "टीबी मुक्त भारत" की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में एएसआई सुरेंद्र, डॉ. नीरज सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। डॉ. गोपाल भारद्वाज ने वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और लक्ष्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि परियोजना इकाई प्रमुख किशोर गौर ने जनसंपर्क और सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर प्रकाश डाला। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए एचपीपीआई के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में किशोर गौर ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। निरमाया परियोजना की टीम : दीपिका, सीमा, शीला, नेहा, ममता, प्रिंस, नितिन, राजेंद्र, जयंता भगत और कौशल ने सभी को जलपान एवं पानी वितरित किया।

घोटाले में 112 करोड़ की संपत्ति जब्त

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने मेसर्ज रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड घोटाले में इस कंपनी के पूर्व निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों, उनसे जुड़ी कंपनियों और पूर्व आरपी के नाम पर दर्ज 112 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। यह संपत्तियां फरीदाबाद, रोहतक, मोहाली आदि में भूखंड, फ्लैट, कृषि भूमि और दुकान के रूप में हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 19 मार्च को विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष इस इंडस्ट्रीज के पूर्व निदेशकों और निलंबित प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता, कंपनी के पूर्व आरपी अरविंद कुमार के साथ-साथ 25 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करवाई थी। इनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने जांच शुरू की है। इसमें पता चला कि इन अपराधों की वजह से बैंकों को करीब 236 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

गुरुग्राम निगम ने करीब ₹350 करोड़ का संपत्तिकर वसूला

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| प्रदेश में संपत्तिकर वसूलने के मामले में गुरुग्राम नगर निगम ने पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से 30 मार्च 2026 तक के जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम निगम ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए करीब 350 करोड़ रुपये का संपत्तिकर वसूल कर अपने खजाने को मजबूत किया है।

वहीं, फरीदाबाद नगर निगम करीब 117 करोड़ रुपये की शानदार वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अब शहर में रुके हुए विकास कार्यों की राह काफी आसान हो जाएगी। पूरे प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों ने मिलकर कुल 1044 करोड़ रुपये का भारी-भरकम संपत्तिकर इकट्ठा किया है, जिसमें अकेले गुरुग्राम का योगदान सबसे ज्यादा है। इस बार निगम की इस शानदार सफलता के पीछे आधुनिक तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी वसूली के बावजूद गुरुग्राम में अब भी करीब 500 करोड़ रुपये का संपत्तिकर लोगों पर बकाया है, जिसे वसूलना निगम के लिए अगली बड़ी चुनौती होगी। निगम इसकी जल्द वसूली करेगा। नगर निगम के इतिहास में यह पहली बार है जब संपत्तिकर जमा करवाने के लिए आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। एआई की मदद से निगम ने शहर के लाखों बकायेदारों के मोबाइल फोन पर सटीक और समयबद्ध तरीके से संदेश भेजे।

शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी : आयुक्त

गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि निगम द्वारा डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे अधिकतम राजस्व संग्रह संभव हो सका। यह रिकॉर्ड संग्रह नगर निगम की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा और शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

जमीन हुई 'सोना': कई इलाकों में 15 से 75% महंगी हुई जमीन, पर 65% जनता को राहत

गांवों में उछालः आर्यनगर में 2.41 करोड़ प्रति एकड़ पहुँचा रेट, खेती की जमीन भी हुई कीमती

हिसार (राजधानी चौपाल) | अगर आप शहर के पॉश इलाकों में घर बनाने या दुकान खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए कलेक्टर रेट का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें आवासीय, व्यवसायिक और कृषि भूमि की कीमतों में 15 प्रतिशत से लेकर 75% तक की भारी बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि शहर के लगभग 65% इलाकों में रेट नहीं बढ़ाए गए हैं।

प्रशासनिक प्रस्ताव के अनुसार, सेक्टर 24 में रहने का सपना अब और भी महंगा हो जाएगा। यहाँ आवासीय रेट में रिकॉर्ड 60% की वृद्धि की गई है, जिससे प्रति वर्ग गज की कीमत ₹39,200 से बढ़कर सीधे ₹62,720 पर पहुँच गई है। वहीं, शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र परिजात चौक के रेट में 45 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। यहाँ अब कीमतें 1.50 लाख से बढ़कर 2,17,500 रुपये प्रति वर्ग गज प्रस्तावित हैं। शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं। गैर-मुमकिन कृषि भूमि के रेट में आर्यनगर और अग्रोहा जैसे क्षेत्रों में 75% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। आर्यनगर में जमीन के रेट 1.38 करोड़ से बढ़कर 2.41 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुँच गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि इन इलाकों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों और डिमांड के कारण रेट बढ़ाना जरूरी हो गया था।

यहाँ नहीं बढ़े रेटः अर्बन एस्टेट, मॉडल टाउन, ऋषि नगर, सूर्य नगर और बीड़ क्षेत्र की कृषि भूमि के रेट फिलहाल फ्रीज रखे गए हैं। इससे इन कॉलोनियों के निवासियों पर रजिस्ट्री के दौरान कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

सेक्टर 24 में 100 गज का प्लॉट खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी के 1.64 लाख अधिक लगेंगे

एक अप्रैल से नये कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि की कीमतों में 15 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। शहर के सेक्टर 24 में रहने के लिए 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं तो पुरुष खरीदार को 7 फीसद स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से अब 1 लाख 64 हजार 640 रुपए अधिक चुकाने होंगे। यहां आवासीय रेट में 60% की वृद्धि प्रस्तावित है। जिससे रेट 39,200 से बढ़कर 62,720 रुपए प्रति वर्ग गज पर पहुंच गए हैं। मॉडल टाउन में 100 गज के 784 और एलसी-2 राज दरबार में 1 लाख 13 हजार 400 रुपए अधिक चुकाने होंगे।

अब चौधरीवास टोल पर कार के 5 और बाडोपट्टी टोल पर 10 अधिक लगेंगे

हिसार | जिला हिसार से दो राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 9 और एनएच 52 गुजरते हैं। इन दोनों राजमार्गों पर चार टोल प्लाजा हैं। रामायण-मय्यड़, लांधड़ी, बाडो पट्टी एवं चौधरीवास शामिल हैं। चारों टोल प्वॉइंट एनएचएआई कार्यालय हिसार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। एनएचएआई ने टोल शुल्क में बढ़ोत्तरी कर नए शुल्क जारी कर दिए हैं। टोल प्वॉइंट से गुजरना अब महंगा हो जाएगा। टोल नाकों पर वाहन चालकों को 5 से लेकर 65 रुपए यानी करीब 5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। नई दरें 31 मार्च यानी आज आधी रात से लागू हो जाएगी। अब वार्षिक पास के भी अधिक पैसे देने होंगे। पहले 3 हजार रुपए लिये जा रहे थे। इस पर एनएचएआई ने ढाई प्रतिशत की वृद्धि की है। अब ये पास लोगों को 3075 रुपए में मिलेगा। कोई वाहन चालक 31 मार्च को पास जारी कराता है तो उसे 75 रुपए का फायदा होगा। 1 अप्रैल से पास पर 75 रुपए अधिक देने होंगे। किसी भी टोल प्लाजा के 20 किमी परिधि के वासियों की घरेलू कार के लिए कम दर पर मासिक पास की सुविधा है। इस वर्ष लोकल मासिक पास की दर 340 के बजाय 350 रुपए निर्धारित की है। संबंधित टोल प्लाजा से संपर्क किया जा सकता है। हिसार एनएचएआई कार्यालय सहायक पुनीत वर्मा ने बताया कि एनएचआई ने 2026-27 के लिए जिले के चारों टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए शुल्क की दरें लागू की है। बढ़ी दरें 31 मार्च आधी रात से सभी टोल प्लाजा पर लागू हो रही हैं।

ओलावृष्टि के कारण गेहूं और अन्य फसल का जल्द सर्वे करवाए सरकार : पंकज बगला

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | नौजवान सभा के ज़िला प्रधान पंकज बगला ने बताया की ओलावृष्टि से कल जो नुकसान हुआ है उसको लेकर आज गांव के किसानो से उनके खेत मे जाकर बातचीत की। गांव बगला के किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण गेहूं और अन्य फसल बिल्कुल ही नष्ट हो गई है किसानों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वे कराया जाए और नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। पंकज बगला ने कहा की सरकार से मांग की है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल शीघ्र खोला जाए और प्रशासन बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाएं। यदि सरकार ने इसमें कोई कोताही बरती तो किसानों के पास आन्दोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा पंकज बगला ने बताया की करीब एक दर्जन गांवों में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए कहर बनकर आई। कल दोपहर के समय गांव चौधरीवाली, घुड़साल, कुतियावाली तेलनवाली, बगला, लाडवी, मोठसरा, सीसवाल, ढाणी सीसवाल, महलसरा, काबरेल सहित अन्य गांवों में तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि के कारण विशेष रूप से गेहूं, सरसों व अन्य खड़ी पर प्रभावित हुई है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का शीघ्र आंकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

अवैध खुदाई से टूटी सीवरेज लाइन, घरों की नींव पर मंडराया खतरा

हिसार (राजधानी चौपाल) | विवेकानंद कॉलोनी, आजाद नगर के निवासियों शमशेर कुंडू, तरुणा, प्रोमिला राजकला, रजनीश, बलबीर सिंह, नीलू, राकेश, रामसिंह आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी गली में कुछ लोग अवैध तरीके से रेनवॉटर ड्रेनेज की पाइप व लाइन गली में डाल रहे हैं, जिससे आसपास के घरों को नुकसान होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हमारे इलाके में सीवरेज लाइन और पानी की सप्लाई लाइन भी तोड़ दी गई है। जिससे गंदा पानी बाहर निकल रहा है। यह पानी धीरे-धीरे हमारे घरों के पास इकट्ठा हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने और घरों की नींव को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। निवासियों ने सम्बंधित अधिकारियों को कई बार सूचित किया परंतु कोई भी अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिये नहीं आया। समस्या ने विकराल रुप धारण कर लिया है।

उपायुक्त महेंद्र पाल ने बरवाला व उकलाना मंडियों का किया निरीक्षण, फसल खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा

हिसार (राजधानी चौपाल) | उपायुक्त महेंद्र पाल ने सोमवार को जिला हिसार के खंड बरवाला तथा उकलाना की अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान मार्केट कमेटी अधिकारियों, आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। उन्होंने कहा कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी फसल की खरीद सुचारू, पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में खरीद एजेंसियों की पर्याप्त व्यवस्था रहे, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार न करना पड़े।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गेट पास व्यवस्था, नापतोल प्रक्रिया तथा नमी मापक यंत्रों की कार्यप्रणाली की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उपकरण सही व पारदर्शी तरीके से कार्य करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा उपायुक्त ने मंडी परिसर स्थित अटल कैंटीन का भी दौरा किया। उन्होंने वहां पर उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और संचालन कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कैंटीन में स्वच्छता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि किसानों और मजदूरों को उचित दर पर अच्छा भोजन मिल सके।

उपायुक्त ने अधिकारियों को कहा कि तिरपाल व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रखी जाएं। उपायुक्त महेंद्र पाल ने फसल आने उपरांत उसका उठान भी समय-समय पर किया जाए ताकि मंडियों में फसल का अनावश्यक स्टॉक जमा न हो और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से मंडियों का निरीक्षण करने और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी फसल मंडियों में लेकर आए। इस अवसर पर विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यूज ब्रीफ

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गीता भारती ने संभाला हिसार मंडलायुक्त का कार्यभार

हिसार (राजधानी चौपाल) | वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गीता भारती ने बुधवार को हिसार रेंज के मंडलायुक्त पद का कार्यभार संभाल लिया।

इस अवसर पर उपायुक्त महेंद्र पाल ने उनका स्वागत किया। मंडलायुक्त ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक मामलों विशेषकर राजस्व कार्यों का त्वरित निपटान करने पर भी विशेष जोर रहेगा। उपायुक्त महेंद्र पाल ने मंडलायुक्त का स्वागत करते हुए कहा कि उनके विविध पदों व क्षेत्रों का कार्य अनुभव और कार्यकुशलता का हिसार जिलावासियों को काफी लाभ मिलेगा।

भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसानः राजेन्द्र सोरखी

हांसी (राजधानी चौपाल) | आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के विभिन्न जिलों जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी और

महेंद्रगढ़ में हुई बेमौसमी बारिश और भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान पर किसानों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रेस को जारी बयान में पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र सोरखी ने सीधे तौर पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों और लगातार हो रही किसानों की अनदेखी के कारण हरियाणा का अन्नदाता बेहाल है।

अमर कुकड़ेजा मनोहर मोर्चा के जिला अध्यक्ष, सादिका अरोड़ा हिसार महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा बनीं

हिसार (राजधानी चौपाल) | मनोहर मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक बैंक कॉलोनी स्थित मोर्चा के संस्थापक सुभाष ढींगड़ा के आवास पर हुई जिसमें

कोर कमेटी के सभी सदस्यों के अतिरिक्त विशेष निमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से तीन सदस्यों को मनोहर मोर्चा में विशेष दायित्व देने का निर्णय लिया गया। इनमें अमर कुकड़ेजा को जिला हिसार का अध्यक्ष, सादिका अरोड़ा को हिसार महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा व विष्णु सोनी को हिसार युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उपस्थित सदस्यों ने नये पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मनोहर मोर्चा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भरपूर योगदान दें। बैठक में हरीश चौधरी, अशोक गांधी, अंबिका प्रसाद, बलबीर नेहरा, दिनेश आर्य, नरेश मेहता, कपिल ठकराल, सुशील मेहता, डिम्पल तनेजा, मिनाक्षी आदि उपस्थित रहे।

बीडी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल में हवन के साथ नये सत्र का शुभारंभ

हिसार (राजधानी चौपाल) | बीडी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल में नये सत्र के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा ईश वंदना की गई। विद्यालय परिसर मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। मंत्रोच्चारण के साथ अध्यापकवृंद व छात्रों ने आहुतियां दी। बच्चों का अनुशासन देखते ही बनता था। मंत्रोच्चारण करते हुए शास्त्रीजी ने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढऩे का आशीर्वाद दिया। विद्यालय की डायरेक्टर डॉ. आस्था भुटानी ने हवन का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को बताया कि हवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजू ने बच्चों को परिश्रम करते रहने के लिये प्रेरित किया। अंत में बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया।

दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट : विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन का व्यावसायिक प्रशिक्षण

हिसार (राजधानी चौपाल) | राजकीय महाविद्यालय हिसार के मनोविज्ञान विभाग में दिव्यांग एकाधिकार पुनर्वास ट्रस्ट के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन विषय पर एक उच्चस्तरीय एवं व्यवहारिक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एम.ए. मनोविज्ञान प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा बी.ए. के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक प्राध्यापक डॉ. चंद्रकांत गोरसी के स्वागत अभिभाषण से हुआ। इस मौके पर कार्यशाला के मुख्य प्रशिक्षक राजपाल सिंह बासनीवाल एवं सह-प्रशिक्षक डॉ. निधि कालरा ने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, उसके प्रमुख प्रकारों, निर्धारक कारकों तथा उसके जीवन पर पडऩे वाले व्यापक प्रभावों के विषय में वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अवगत कराया।

हिसार में एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर प्रशासन की नजर, नम्बर जारी

हिसार (राजधानी चौपाल) | उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा है कि जिले में एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता व आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जांच टीमों का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से बाजार में आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं। इसके अलावा सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए कार्यालय उपायुक्त प्रथम तल के कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 01662-241034 तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के हेल्पलाइन नंबर 01662-233944 जारी किया गया है। इन नंबर पर कोई भी व्यक्ति गैस या पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित शिकायत या सुझाव दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में एलपीजी गैस व अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित आपूर्ति हो रही है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

हकृवि कुलपति के निर्देशन में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी की विशेष मुहिम

हिसार (राजधानी चौपाल) | चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में कपास के उत्पादन व क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय द्वारा भिवानी व हिसार जिले के विभिन्न गांवों नंगथला, ढाणी धिरजा, धूलकोट और सदलपुर में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक विषय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में किसानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

शिविर के समापन अवसर में किसानों को संबोधित करते हुए अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग ने किसानों को कपास फसल की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों से उन्नत तकनीकें अपनाकर कपास का औसत उत्पादन बढ़ाने व बैटरी चालित पंप का किसान हित में उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय आपकी तकनीकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

कपास अनुभाग के अध्यक्ष डॉ. करमल ने शिविर में कपास फसल से जुड़ी तमाम जानकारियां किसानों को दी। कार्यक्रम में हिसार जिले के विभिन्न गांवों के 30 पुरूष व महिला किसानों को बैटरी चालित स्प्रे पम्प व सुरक्षा किट प्रदान किए गए।

अग्निपथ योजना : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथि को 10 तक बढ़ाया

हिसार (राजधानी चौपाल) | भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना-2027 के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बढ़ाकर 10 अप्रैल रात 11:59 बजे तक कर दी गई है। गौरतलब है कि आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी।

यह जानकारी देते हुए हिसार सेना भर्ती कार्यालय से भर्ती निदेशक ने बताया कि हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिलों के योग्य युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 250 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार अग्निवीर की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं पास) तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास) शामिल हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी प्राथमिकता का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि भर्ती वर्ष 2027 के लिए चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित होगी।

नाई की मेहनत रंग लाईः सदलपुर के संदीप टाक की बेटियों ने रचा इतिहास

डिंपल ने 200 में से 200 और योगिता ने 600 में से 599 अंक किया हासिल

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | मेहनत, संघर्ष और लगन की मिसाल बने हैं गांव सदलपुर के रहने वाले संदीप टाक, जो मंडी आदमपुर में हेयर सैलून का काम करते हैं। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी—और आज उनकी यही मेहनत रंग लाई है। संदीप टाक की दोनों बेटियां गांव सदलपुर स्थित स्कूल में पढ़ाई करती हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं।

संदीप टाक की छोटी बेटी डिंपल, जो पांचवीं कक्षा की छात्रा है, ने इस बार कमाल कर दिया। उसने 200 में से पूरे 200 अंक हासिल किए और हर विषय में टॉप करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

वहीं बड़ी बेटी योगिता, जो आठवीं कक्षा में पढ़ती है, ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 600 में से 599 अंक प्राप्त किए। इतनी शानदार उपलब्धि के बाद योगिता पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बनी हुई है।

संदीप टाक रोज़ाना मंडी आदमपुर में मेहनत करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत न होने के बावजूद उन्होंने बेटियों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका मानना है कि शिक्षा ही वह रास्ता है, जो बच्चों का भविष्य बदल सकती है।

आज संदीप टाक की बेटियां न सिर्फ अपने परिवार बल्कि गांव सदलपुर का भी नाम रोशन कर रही हैं। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। यह साबित हो गया है—अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।

गुजवि में सर्कल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता के महाकुंभ का हुआ शानदार आगाज

खेल को हमेशा खेल भावना, धैर्य व अनुशासन में रहकर खेलना चाहिए : कुलसचिव

हिसार (राजधानी चौपाल) | गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (गुजविप्रौवि) के महाराणा प्रताप स्टेडियम में अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय सर्कल स्टाईल कबड्डी (महिला) एवं (पुरुष) प्रतियोगिता के महाकुंभ का शानादर आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रस्तुत हरियाणवी नृत्य सारा देश सुणेगा हरियाणें की, देशां म्ह देश हरियाणा जित दूध-दही का खाणा व पंजाबी गिद्दा मंजीरा टुंग-टुंग करदा ने उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर खिलाड़ियों द्वारा शानदार मार्च पास्ट भी प्रस्तुत किया गया।

प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच एल.एन.आई.पी.ई ग्वालियर तथा डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय राजस्थान के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में एल.एन. आई.पी.ई ग्वालियर की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का शुभारम्भ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. विजय कुमार ने मंच से विश्वविद्यालय तथा ए.आई.यू. के ध्वज का ध्वजारोहण करके किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि वह खिलड़ियों के जोश व जज्बे को सलाम करते हैं। क्योंकि मेहनत व ईमानदारी से ही मुकाम हासिल किया जा सकता है। खेल को हमेशा खेल भावना, धैर्य व अनुशासन में रहकर खेलना चाहिए। क्योंकि हार या जीत कोई मायने नही रखती है। एक बार की हार हमें ओर अधिक मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करने की प्रेरणा देती है।

विशिष्ट अतिथि एशियन कबड्डी खिलाड़ी व गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट कृष्ण गोदारा ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स प्रो. आशीष अग्रवाल ने देश के विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में मिनी भारत की तस्वीर दिखाई दे रही है। जिसमें देश के अलग-अलग प्रान्तों के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी अपना दम खम दिखाने के लिए आए हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग सचिव तथा खेल निदेशक डा. शशि भूषण लूथरा ने प्रतियोगिता के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी व रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सीएम ने तोशाम में 107 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया

आपदा में अवसर तलाशता है विपक्ष, बयानबाजी के बजाय सरकार से सहयोग करेः सीएम नायब

चंडीगढ़/ भिवानी/तोशाम (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और खेती से जुड़े होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को होने वाले नुकसान को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने बताया कि पटवारी और तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को सरकार मुआवजा राशि देगी। इस काम के लिए अगले एक सप्ताह में प्रदेशभर में 2,500 पटवारी गांव-गांव जाकर बिना पर्ची और खर्ची के कार्रवाई करेंगे।

सीएम मंगलवार को तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव समारोह के दौरान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उन्नत सिंचाई उत्सव मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दे रही है। अब तक हरियाणा में 1 लाख 80 हजार युवाओं को यह सुविधा दी जा चुकी है, जिसमें भिवानी जिले के 25,000 युवा शामिल हैं। सीएम ने कहा कि 28 मार्च से प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू हुई है, जो मंडियों में एमएसपी से भी ऊपर रेट पर बिक्री हो रही है। सरकार रबी की फसल के एक-एक दाने को खरीदने का काम करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीदने का काम कर रही है। अम्बाला और नारायणगढ़ में यह प्रक्रिया चल रही है और एक सप्ताह के अंदर तोशाम में भी आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति अपनी भूमि देने पर विचार करें। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रक्रिया है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। सरकार भूमि का उचित रेट और सम्मानजनक मूल्य देगी।

श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में शैक्षणिक भवन का लोकार्पण

चंडीगढ़ सीएम नायब सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर नए शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। वहीं, सीएम ने भगवान महावीर जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में भगवान महावीर को पुष्प अर्पित कर नमन किया।

बोले-विपक्ष राजनीतिक रोटी न सेंके

सीएम नायब सैनी ने कहा कि कोई भी आपदा हो पीएम मोदी देश के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। किसी देश का युद्ध हो, पीएम मोदी वहां से हर भारतीय को सुरक्षित लाते हैं, लेकिन विपक्षी आपदा में भी अवसर वसर ढूंढते हैं और राजनीति करते हैं। विपक्ष राजनीतिक रोटी न सेंके, लोगों में भ्रम न फैलाएं। विपक्ष भ्रम फैलाता है, लेकिन मोदी सरकार देश व प्रदेश में पेट्रोल डीजल या गैस की कमी नहीं आने देंगे। कालाबाजारी पर रोक लगाई गई और एफआईआर दर्ज करवाई गई। गैस पाइपलाइन बिछाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। ऐसे हालातों में में विपक्ष को गलत बयानबाजी करने के बजाय सरकार का सहयोग करना चाहिए। सीएम ने तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव के दौरान 107 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया।

निजी स्कूलों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 31.88 करोड़ जारी

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | प्रदेश सरकार ने 134-ए के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एवं बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर अपने वादे को पूरा किया है। विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के सात जिलों अम्बाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक के निजी विद्यालयों को लाभ प्राप्त हुआ है। यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना निरंतर प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 134-ए के तहत दी जा रही यह सहायता उसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

न्यूज ब्रीफ

चोर दरवाजे से एमएसपी खत्म करने की साजिश कर रही सरकारः राव नरेंद्र

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने राज्य में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नए नियमों को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए आरोप लगाया कि ये किसानों को एमएसपी से वंचित करने की साजिश है। राव ने कहा कि ट्रॉली रजिस्ट्रेशन, फोटो अपलोड, समय सीमा और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे नियमों से मंडियों में भीड़ और देरी बढ़ेगी। उन्होंने ने कहा कि तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद अब 'चोर दरवाजे' से एमएसपी खत्म करने की साजिश चल रही है। ओलावृष्टि से पहले ही प्रभावित किसानों पर इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और फसल खराब होने का खतरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद लक्ष्य घटाकर सरकार जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। समस्याओं का समाधान न होने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

चोर दरवाजे से एमएसपी खत्म करने की साजिश कर रही सरकारः राव नरेंद्र

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने राज्य में गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नए नियमों को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए आरोप लगाया कि ये किसानों को एमएसपी से वंचित करने की साजिश है। राव ने कहा कि ट्रॉली रजिस्ट्रेशन, फोटो अपलोड, समय सीमा और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे नियमों से मंडियों में भीड़ और देरी बढ़ेगी। उन्होंने ने कहा कि तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद अब 'चोर दरवाजे' से एमएसपी खत्म करने की साजिश चल रही है। ओलावृष्टि से पहले ही प्रभावित किसानों पर इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और फसल खराब होने का खतरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद लक्ष्य घटाकर सरकार जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। समस्याओं का समाधान न होने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

प्रदेश में बढ़ती रंगदारी व धमकी की घटनाओं से व्यापारियों में भय : सैलजा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | प्रदेश में हाल ही में सामने आई रंगदारी व धमकी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने चिंता जताई है। अम्बाला, जुलाना व अन्य क्षेत्रों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें व्यापारियों को फोन कॉल, विदेशी नंबरों व अन्य माध्यमों से जान से मारने की धमकी देकर लाखों की रंगदारी मांगी जा रही है। अम्बाला की सरस्वती कॉलोनी में इमिग्रेशन कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई व उससे 50 लाख की मांग की गई। आरोपियों ने कारोबारी और उनके परिवार को डराने के लिए उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीरें भेजकर मानसिक रूप से प्रताडित किया। जुलाना में जींद-रोहतक मार्ग स्थित भट्ठा संचालक से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी देते हुए जल्द पैसे की व्यवस्था करने को कहा।

प्रदेश में बढ़ती रंगदारी व धमकी की घटनाओं से व्यापारियों में भय : सैलजा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | प्रदेश में हाल ही में सामने आई रंगदारी व धमकी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने चिंता जताई है। अम्बाला, जुलाना व अन्य क्षेत्रों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें व्यापारियों को फोन कॉल, विदेशी नंबरों व अन्य माध्यमों से जान से मारने की धमकी देकर लाखों की रंगदारी मांगी जा रही है। अम्बाला की सरस्वती कॉलोनी में इमिग्रेशन कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई व उससे 50 लाख की मांग की गई। आरोपियों ने कारोबारी और उनके परिवार को डराने के लिए उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीरें भेजकर मानसिक रूप से प्रताडित किया। जुलाना में जींद-रोहतक मार्ग स्थित भट्ठा संचालक से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी देते हुए जल्द पैसे की व्यवस्था करने को कहा।

गुर्जर पंचायत : शादियों में फिजूलखर्ची का विरोध, अगले सीजन से डीजे पर पाबंदी लगाई

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल) | गुर्जर समाज में शादियों में फिजूलखर्ची को लेकर रविवार को पंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत राजेश पायलट चौक स्थित गुर्जर भवन में हुई। पंचायत में शादियों के आगामी सीजन (नवंबर) से डीजे बजाने पर पूर्णतयाः प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि, इस पंचायत में दहेज पर पाबंदी लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन शादियों में भात न्यौतने व भात भरने के दौरान होने वाली फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने, मंढा (बूरा खाने) समधी की मिलाई में 101 रुपए, बढ़ समधी को 151 रुपए तक देने का निर्णय लिया। महापंचायत की अध्यक्षता अभयपुर के वयोवृद्ध सरपंच स्वामी खटाना ने की। वरिष्ठ समाज सेवी अंतराम तंवर ने बताया कि गुरुग्राम जिले में शादियों में फिजूलखर्च बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर समाज को एकजुट कर अहम फैसले लेने के लिए यह पंचायत की गई। पंचायत में गुर्जर बाहुल गांवों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि नवंबर से शुरू होने वाले शादियों के सीजन से यह फैसले लागू किए जाएंगे। वहीं इन फैसलों को लागू करवाने के लिए 51 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है, जो हर गांव में पहुंचकर लोगों को इन फैसलों के बारे में जानकारी देकर फैसलों पर अमल कराने का काम करेगी।

मंडी को हाई सिक्योरिटी जेल बना रहेः हुड्डा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा की रीति-नीति बन गई है कि वो हर बार किसानों को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ़ लाती है। इस बार गेहूं खरीद के लिए नया नियम बनाया गया कि ट्रैक्टर की नंबर प्लेट की फोटो समेत किसानों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। किसान को वेरिफाई करने के लिए 3-3 गारंटर भी चाहिए होंगे। मानो ये अनाज मंडी नहीं, बल्कि कोई हाई सिक्योरिटी जोन या जेल हो। इससे मंडियों में सरकारी खरीद पहले ही दिन ठप हो गई। कारण ये कि सरकार द्वारा लागू किए नियम व ई-खरीद पोर्टल दोनों फेल हो गए। आढ़ती एसोसिएशन ने बताया है कि एक गेट पास बनाने में 10 से 15 मिनट लग रहा है, इससे एक दिन में सीमित संख्या में ही किसानों की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। मंडियों में आज ना बारदाना है, ना तिरपाल, ना लेबर, ना किसानों के लिए कोई सहूलियत और ना ही अबतक ट्रांसपोर्ट के टेंडर हुए हैं। पार्टी एक तरफ जहां मई माह में पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय बैठकें करेगी, वहीं कांग्रेस विधायक अब मंडियों में उतरेंगे। तय हुआ कि गेहूं और सरसों की खरीद में किसानों को आ रही दिक्कतों को जानने के लिए तमाम विधायक प्रदेशभर की मंडियों का दौरा करेंगे और किसानों की आवाज को उठाएंगे।

महज आरोपों की गंभीरता से बेल रद्द नहीं, नई परिस्थिति जरूरीः हाई कोर्ट

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े केस में स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता या बरामदगी न होना, बेल रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। जस्टिस सुमित गोयल ने फैसले में कहा कि बेल रद्द करने के लिए साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने अपनी आजादी का दुरुपयोग किया है या कोई नई परिस्थितियां सामने आई हैं। कोर्ट ने नूंह जिले में दर्ज घर में घुसपैठ के मामले में यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में जमानत देने और जमानत रद्द करने के बीच अंतर रेखांकित किया। कहा कि दोनों स्थितियां अलग-अलग कानूनी दायरे में आती हैं व जमानत रद्द करने के मानदंड कहीं अधिक सख्त होते हैं, इनके लिए ठोस साक्ष्य जरूरी है।

पीएम मोदी रैली में जाने वाले वाहनों में भरे ईंधन की देनदारी अब भी बाकी

1 वर्ष पहले हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे

झज्जर (राजधानी चौपाल) | हिसार में 14 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन समारोह के लिए आए थे। प्रशासन के द्वारा रैली में शामिल होने के लिए विभिन्न निजी वाहनों को अलग-अलग जिलों से हिसार भेजा था। समारोह में जाने वाली गाड़ियों में ईंधन भरा गया था। उनकी पेमेंट करीब 1 साल बाद भी नहीं हुई है।

बताया गया कि हिसार, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर समेत अन्य जिलों के 10 से ज्यादा पेट्रोल पंपों का करीब 8 लाख रुपए बकाया है। अब पेमेंट कैसे होगी, इसकी जानकारी पेट्रोल पंप संचालकों को नहीं है। झज्जर से तो 1 पेट्रोल पंप संचालक ने इसके लिए सीएम विंडो में भी शिकायत दी है, लेकिन उसका जवाब भी अब तक नहीं

मिल सका है। झज्जर के जाखोदा में ओम फिलिंग स्टेशन का 1 लाख 29 हजार रुपए बकाया है। रोहतक के चार पेट्रोल पंपों का 2 लाख 75 हजार रुपए प्रशासन से लेना है। हिसार और यमुनानगर के पंप संचालकों का भी का पैसा बकाया है। झज्जर डीएफएससी कार्यालय के कोऑर्डिनेटर सुमित हुड्डा ने बताया कि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के जाखोदा स्थित ओम फिलिंग स्टेशन की पेमेंट 1,29,000 के करीब बाकी है। इसके लिए हमने हिसार डीसी ऑफिस में बिल भेज रखा है।

पीजीटी कम्प्यूटर साइंस नॉलेज टेस्ट 10 मई को

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | पीजीटी कम्प्यूटर साइंस भर्ती का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 10 मई को आयोजित किया जाएगा। आवेदन में निर्धारित पदों से चार गुना से कम आवेदन होने पर स्क्रिनिंग टेस्ट नहीं कराया गया है।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नॉलेज टेस्ट की तारीख निर्धारित करने संबंधी नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि 2019 में पीजीटी कम्प्यूटर साइंस की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। पहले एचएसएससी और फिर यह भर्ती एचपीएससी के पास गई। फरवरी में ही इसका परिणाम आया तो काफी चौंका गया। क्योंकि 1711 पदों पर सिर्फ 39 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। ऐसे में कमीशन ने उसी दिन बाकी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांग लिए थे। इनमें 1,594 हरियाणा और 78 पद मेवात कैडर के हैं।

हरियाणा के कई विभागों का पैसा सालों से चालू खाते में पड़ा था, अब हो रही जांच

खातों का मिलान तेज, चंडीगढ़ के बिजनेसमैन का कनेक्शन सामने आया

पंचकूला (राजधानी चौपाल) | हरियाणा के सरकारी विभागों में करोड़ों रुपए के गबन के बड़े खेल का खुलासा होने के बाद अब सरकार ने 'ऑपरेशन क्लीन' शुरू कर दिया है। वित्त विभाग सभी विभागों के बैंक खातों का 'खाका' तैयार कर रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कई विभागों ने लंबे समय तक करोड़ों रुपए करंट अकाउंट में रखे, जिनका गलत इस्तेमाल हुआ। सरकार अब उन विभागों की सूची तैयार कर रही है जिनके फंड के साथ छेड़छाड़ की गई है। बैंकों के इस गबन मामले की जांच के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में कोटक बैंक के अधिकारी नगर निगम कमिशनर आईआरपीएस विनय कुमार के ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही उनके पास करोड़ों की एफडी रिन्यू करवाने पहुंचे थे। बैंक अधिकारी ने सबसे ज्यादा एफडी पर साढ़े 8% ब्याज देने की बात कही थी। 18 फरवरी को आईडीएफसी बैंक में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। 18 फरवरी को ही निगम कमिशनर ने सरकार के अगले निर्देश तक एफडी को रिन्यू करने पर रोक लगा दी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

मामले में एक और गिरफ्तारी...

नगर निगम पंचकूला में करोड़ों रुपए के गबन मामले की जांच में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने राजपुरा निवासी कपिल को सरहिंद से गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार, कपिल के बैंक खाते में नगर निगम के खाते से 2.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। राजपुरा में रजत धारा ने कुछ समय पहले मोबाइल की दुकान खोली थी। वहां पर कपिल एक निजी टेलीकॉम कंपनी में बतौर रिलेशनशिप मैनेजर कार्यरत था। कपिल का रजत की दुकान पर आना जाना था। वहीं दोनों की दोस्ती हुई।

विधायकों पर कार्रवाई केवल हुड्डा की पसंद ना पसंद का खेलः बड़ौली

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | राज्यसभा चुनाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चुनाव लड़ा और भाजपा ने उसे सपोर्ट किया। कांग्रेस विधायकों ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद को दिखाकर वोट डाले थे। कांग्रेस के विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिए। कांग्रेस पार्टी विधायकों को नोटिस भेजने और विधायक दल की बैठक के नाम पर ड्रामा कर रही है। विधायकों पर कार्रवाई केवल भूपेंद्र हुड्डा की पसंद ना पसंद का खेल है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक सोच की कमी है। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का हिस्सा है।

एमएसपी पर गेहूं-सरसों नहीं खरीदने की साजिश रच रही सरकारः सुरजेवाला

कहा- इतनी शर्त लगा दीं, उन्हें पूरा करना किसानों के लिए मुश्किल

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार 'चोर दरवाजे' से फसलों की एमएसपी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रही है। सुरजेवाला ने हाल में जारी शर्तों पर सवाल उठाए। पहली शर्त में किसान को फसल उसी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लानी होगी, जिस पर नंबर हो। मंडी गेट पर ट्रैक्टर व नंबर की फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, फिर गेटपास मिलेगा। सुरजेवाला ने पूछा कि क्या हर किसान पर ट्रैक्टर-ट्रॉली है? यदि किसान अलग-अलग समय पर अलग-अलग वाहनों का उपयोग करता है तो क्या पोर्टल उन्हें स्वीकार करेगा? दूसरी शर्तः मंडी फसल लाने का समय सुबह 6 से शाम 8 बजे तक को लेकर है। सुरजेवाला का तर्क है कि किसान ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं, जो दिन-रात चलती हैं। इस पाबंदी से मंडियों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगेंगी। तीसरी शर्त में फसल बेचने के समय किसान या उसके द्वारा नामित 3 व्यक्तियों में से किसी को बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने के लिए मंडी में मौजूद रहना होगा। सुरजेवाला ने कहा कि कटाई के समय किसान खेत में व्यस्त रहता है व परिवार के सदस्य या मजदूर फसल लेकर मंडी जाते हैं। उन्होंने पट्टा दिखाने, और मंडी से फसल बाहर ले जाने के लिए तीन अधिकारियों के हस्ताक्षर जैसी शर्तों को 'क्रूर षडयंत्र' बताया।

मंडियों में सरकारी खरीद ठपः ढांडा

'आप' नेता अनुराग ढांडा ने मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद के पहले दिन फैली अव्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-खरीद पोर्टल ध्वस्त होने, बारदाने और लेबर की कमी के कारण 90% मंडियों में खरीद ठप रही। ढांडा के अनुसार, प्रदेश भर में भारी आवक के बावजूद 5% खरीद भी नहीं हो पाई, जिससे तपती धूप में खड़ा किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर है।

रामायण पर पूर्व सांसद का विवादित बयान

कथाएं मानसिक रूप से गुलाम बना रहीं, वाचक लाखों कमा रहेः सैनी

फरीदाबाद (राजधानी चौपाल) | कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने रविवार को धार्मिक मान्यताओं व रामायण पर विवादित बयान दिया।

उन्होंने कहा कि रामायण को काल्पनिक रूप में पेश किया गया है, जबकि असली रामायण का दावा ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक में किया गया है, जिसे पेरियार ईवी रामासामी ने प्रचारित किया था।

सैनी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 1976 को इस विषय में फैसला भी दिया था। इसमें कहा गया कि ललई ने जो लिखा वह सही तथ्य है। सैनी ने धार्मिक कथाओं व संत महात्माओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने का माध्यम बन गए हैं। कथावाचक लाखों रुपए लेकर कथा करते हैं।

10 सिर के व्यक्ति को रावण बनाकर दिखाया गया, पर ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। ये केवल कहानियां हैं। इनसे लोगों को मुद्दों से भटकाया जाता है। 4 अप्रैल को फरीदाबाद में मनाए जाने वाले अशोक सम्राट पर आधारित कार्यक्रम को लेकर राजकुमार यहां के सैनी समाज को न्योता देने पहुंचे थे। सैनी ने कहा कि उनके समाज के लोगों को काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखा गया है। इसलिए उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा।

स्वीपिंग मशीनों की निगरानी के लिए कैमरे लगेंगे : सीएम

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | स्वीपिंग मशीनों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। इन मशीनों पर 4 कैमरे लगाए जाएंगे। 1 आगे, 1 ऊपर, 1 नीचे व 1 पीछे की ओर। यदि सफाई के दौरान मशीन के नीचे लगा सेंसर बंद पाया जाता है तो एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाएगा।

अब एजेंसियों को हर माह बिल के साथ काम से जुड़े वीडियो फुटेज भी जमा करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी जांच हो सके। इस व्यवस्था में 1250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पेनल्टी का प्रावधान किया है, इससे एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी व काम में लापरवाही नहीं होगी। यह जानकारी सोमवार को स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने सीएम नायब सिंह सैनी को दी।

वे सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अफसरों की बैठक ले रहे थे। सीएम ने बारिश से पहले होने वाली ड्रेन सफाई, जल निकासी व्यवस्था और सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने हरियाणा भर में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने के लिए स्थान ढूंढने के निर्देश दिए है। बारिश में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या सामने आती है, इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जहां-जहां जल निकासी में दिक्कत है, उन स्थानों की पहचान कर वहां वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ऐसे स्थानों पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विकल्प तलाशे जाएं, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके व जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके।

प्रदेश में वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा पूरा और अपडेटेड डेटा तैयार किया जाए। इसमें ये जानकारी शामिल हो कि कहां वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं, उनमें से कितने सही से काम कर रहे हैं व कहां इन्हें लगाने की आवश्यकता है।

सीएम ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में इन सिस्टम्स को सही तरीके से लागू किया जाए और जहां यह अभी तक नहीं लगे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर इन्हें स्थापित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में इसे विशेष रूप से लागू करना सुनिश्चित किया जाए।

राज्यसभा चुनाव को लेकर जजपा नेता व कांग्रेस सांसद ने भाजपा को घेरा

अजय बोले- मनोहर ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जेपी ने भी कहा- भाजपा ने धनबल की राजनीति की

हिसार/चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिए जाने का दावा किया है। इस पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा धनबल व खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। अजय स्वयं बयान दे रहे हैं कि मनोहर ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया और भाजपा के अलावा 9 कांग्रेस विधायकों के समर्थन की बात भी कही। जेपी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि जजपा भी भाजपा के लिए ही काम कर रही है।

जेपी ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने धनबल और दबाव की राजनीति कर सरकार बनाई थी। सिरसा में गोपाल कांडा ने विधानसभा चुनाव के बाद बयान दिया था कि मनोहर ने उन्हें इनेलो की मदद के लिए कहा था। इससे सिद्ध होता है कि ये सभी भाजपा के लिए राजनीति कर रहे हैं।

क्रॉस वोटिंग वालों पर कार्रवाई करने से पहले आज विधायकों का मन टटोलेगी कांग्रेस : चंडीगढ़ राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक सोमवार को दिल्ली में इकट्ठा होंगे। क्रॉस वोटिंग व अवैध वोटों की गरम सियासत के बीच कांग्रेस की यह पहली विधायक दल की बैठक होगी। इसमें चर्चा का मुख्य विषय राज्यसभा का चुनाव ही रहेगा। क्योंकि जहां क्रॉस वोटिंग के आरोपी 5 विधायकों की बैठक में नो एंट्री रखी गई है, वहीं अब मामले में पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की भी जल्द बैठक होगी। इसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार होनी है। इससे पहले विधायक दल की बैठक को अहम माना जा रहा है। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीनियर नेता विधायकों का इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर मन टटोल सकते हैं। कुछ विधायकों ने चुनाव के बाद मीडिया के सामने खुलकर बात कहते हुए पार्टी पर ही आरोप लगाकर नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि दो विधायक तो पहले क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों के नाम सार्वजनिक करने के लिए चंडीगढ़ में ही पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। एक विधायक ने पार्टी में चापलूसों की इज्जत की बात कही थी। भूपेंद्र हुड्डा ने इन विधायकों को मनाया भी था। इस बैठक में मन टटोलने के बाद विधायकों की सोच को हाईकमान तक भी पहुंचाया जा सकता है। ताकि इस सोच को भी क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों पर होने वाली कार्रवाई में शामिल किया जाए। क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों में शामिल शैली चौधरी, रेनु बाला और जरनैल सिंह ने नोटिस का जवाब भेजकर स्पष्ट किया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। जबकि मोहम्मद इलियास व मोहम्मद इसरायल ने जवाब नहीं दिया।

इसरायल के कार्यक्रम में उनके इलाके में भाजपा सरकार के मंत्री भी पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस इनके खिलाफ कार्रवाई से पहले राज्यसभा चुनाव से फैसले तक की गतिविधियों भी अवश्य जांचेंगी। सूत्रों की मानें तो पार्टी की ओर से कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जिसमें निलंबन कम से कम माना जा रहा है। कार्रवाई पूरी तरह अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट पर ही आधारित होगी। समिति की बैठक अगले माह के पहले सप्ताह में हो सकती है।

मुझे पता था- इनेलो के दो विधायकों के वोट नहीं मिलेंगेः अजय चौटाला

वीडियो में जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा कि मनोहर लाल ने उन्हें राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। कहा था कि कांग्रेस के 9 विधायकों का समर्थन भी मिलेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अजय ने ये भी कहा कि उन्हें यह पता था कि इनेलो के दो विधायकों के वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। जबकि वे तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। अब चौटाला के इस बयान को राजनीति के जानकारी जजपा की भाजपा से दूरी का संदेश देने से जोड़ रहे हैं।

संपादकीय...

कटी फसल पर तेल और गैस की किल्लत का साया...

हरियाणा के खेतों में इन दिनों गेहूं की कटाई और थ्रेसिंग का काम जोरों पर है। किसान साल भर की मेहनत को सहेज कर अनाज के रूप में घर लाने की तैयारी में है। लेकिन अफसोस! जब किसान को अपनी फसल निकालने के लिए सबसे ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, तभी बाजार में ईंधन (डीजल) और रसोई गैस की किल्लत ने उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं।

गेहूं की कटाई और गहाई (थ्रेसिंग) पूरी तरह से ट्रैक्टरों और कंबाइन मशीनों पर निर्भर है। इन मशीनों को चलाने के लिए भारी मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर 'नो स्टॉक' के बोर्ड लटके नजर आ रहे हैं। जहाँ तेल मिल भी रहा है, वहाँ लंबी कतारें लगी हैं। किसान अपना काम छोड़कर खाली कैन लेकर पंपों के चक्कर काट रहा है। डीजल की यह कमी केवल मशीनें नहीं रोक रही, बल्कि किसान की साल भर की उम्मीदों को भी ठप कर रही है। कटाई में एक दिन की देरी का मतलब है, अचानक आने वाले आंधी-तूफान या बेमौसम बारिश के खौफनाक साये में जीना।

ईंधन की यह मार सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की आपूर्ति में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। कटाई के सीजन में घर की महिलाएं खेतों में काम करने वाले मजदूरों और परिवार के लिए खाना तैयार करने में व्यस्त होती हैं। ऐसे समय में गैस सिलेंडर का समय पर न मिलना ग्रामीण महिलाओं के लिए दोहरी मुसीबत बन गया है। लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना इस तपती गर्मी में किसी सजा से कम नहीं है, ऊपर से सूखे भूसे के ढेर के पास आग जलाना आगजनी के खतरे को भी निमंत्रण देता है। कटाई के इस व्यस्त समय में जब हर मिनट कीमती है, तब चूल्हे के धुएं में वक्त बर्बाद करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पहिये को और पीछे धकेलता है।

ईंधन की इस किल्लत ने कालाबाजारी को भी जन्म दे दिया है। मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग महंगे दामों पर डीजल और गैस बेचने की ताक में हैं। 'राजधानी चौपाल' के माध्यम से हम प्रशासन से यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हर बार पीक सीजन में ही आपूर्ति क्यों लड़खड़ाती है? क्या सरकार को यह अंदेशा नहीं था कि अप्रैल में मांग बढ़ेगी? प्रशासन की यह सुस्ती और आपूर्ति विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर किसान की जेब पर डाका डालने जैसा है।

किसान पहले ही प्रकृति की मार से त्रस्त है। अब ईंधन की यह 'मारामारी' उसके सब्र का इम्तिहान ले रही है। यदि समय रहते आपूर्ति सुचारू नहीं की गई, तो अनाज मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खेतों में बर्बाद हो सकता है।

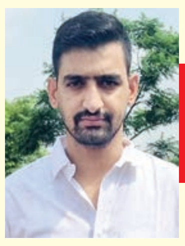

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

एक एकड़ से साढ़े छः एकड़ तक...

एक किसान की अमर कहानी, एक परिवार का संघर्ष

हरियाणा की मिट्टी सिर्फ अनाज ही नहीं उगाती, बल्कि संघर्ष, त्याग और सपनों की ऐसी कहानियाँ भी जन्म देती है जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती हैं। यह कहानी भी उसी मिट्टी से निकली है—एक साधारण किसान की, जिसने अपने खून-पसीने से अपने परिवार का भविष्य लिखा। यह कहानी है मेरे पिताजी किरसन खिचड़ की, मेरी माता बरसी देवी के साथ उनके संघर्ष की, और उस विरासत की, जो मेरे दादाजी राजाराम खीचड़ और दादी जी से हमें मिली।

विरासत की नींवः दादा-दादी का आशीर्वाद

हर मजबूत इमारत की एक गहरी नींव होती है। हमारे परिवार की नींव रखी थी मेरे दादाजी राजाराम खीचड़ और मेरी दादी जी ने। उन्होंने हमें एक एकड़ जमीन गिफ्ट में दी। यह जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक भरोसा थी—कि आने वाली पीढ़ी इसे आगे बढ़ाएगी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही एक एकड़ जमीन आगे चलकर हमारे परिवार की किस्मत बदल देगी।

जन्म और शुरुआती जीवन

मेरे पिताजी किरसन खिचड़ का जन्म 1 जनवरी 1975 को हुआ था। उनका बचपन बहुत साधारण परिस्थितियों में बीता। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारियों को समझ लिया। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहाँ मेरे पिताजी काम करना सीख रहे थे। उन्होंने जीवन को बहुत जल्दी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।

एक एकड़ जमीन और अनगिनत मुश्किलें

शुरुआत में हमारे पास केवल एक एकड़ जमीन थी। आज के समय में यह बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय वही हमारी दुनिया थी। एक एकड़ जमीन से पूरे परिवार का खर्च निकालना आसान नहीं था। इसलिए मेरे पिताजी ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेतों में दिनभर काम करना और शाम को थककर घर लौटना—यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी।

माता-पिता का संघर्षः जब दोनों मजदूर थे

मेरे पिताजी अकेले नहीं थे इस संघर्ष में। मेरी माता बरसी देवी ने भी उनका हर कदम पर साथ दिया। एक समय ऐसा था जब दोनों पति-पत्नी मजदूरी करते थे। दिनभर मेहनत करने के बाद भी घर चलाना मुश्किल हो जाता था। कई बार जरूरतें अधूरी रह जाती थीं। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी।

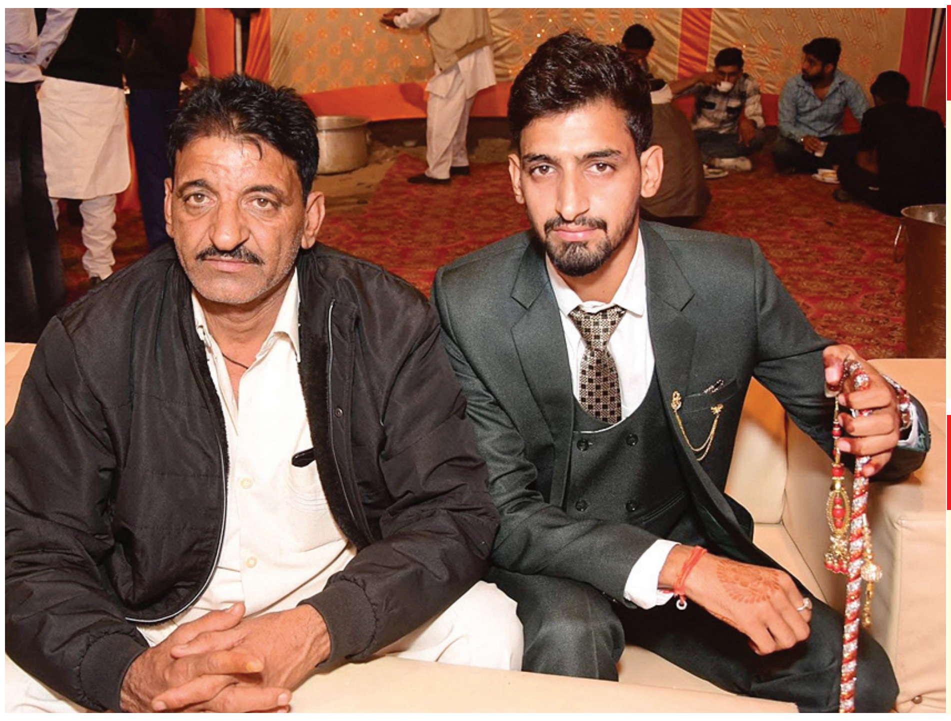

चोट के बावजूद अटूट हिम्मत

मेरे पिताजी के पैर में चोट लगी हुई थी। यह चोट उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। दर्द के बावजूद वे खेतों में काम करते रहे। यह सिर्फ मेहनत नहीं थी—यह उनके परिवार के प्रति उनका समर्पण था।

धैर्य और समझदारी का बड़ा फैसला

किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन होती है। मेरे पिताजी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। जब हमारी एक एकड़ जमीन की अच्छी कीमत मिली, तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धैर्य रखा, सही समय का इंतजार किया और फिर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस जमीन को बेचकर साढ़े छः एकड़ जमीन खरीद ली। यह सिर्फ जमीन खरीदना नहीं था—यह एक नए जीवन की शुरुआत थी।

बदलाव की शुरुआतः जब हालात बदलने लगे

जमीन बढ़ने के साथ-साथ हमारे जीवन में भी बदलाव आने लगा। अब हमारे पास ज्यादा खेती थी, ज्यादा आय थी और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद थी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी। अब जरूरतें पूरी होने लगीं।

सपनों का घर

मेरे पिताजी ने सबसे पहले हमारे लिए एक पक्का मकान बनवाया। वह मकान सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि उनके वर्षों की मेहनत और सपनों का परिणाम था। उस घर में सिर्फ दीवारें नहीं थीं, उसमें हमारे परिवार की खुशियाँ बसती थीं।

बच्चों की जिम्मेदारीः शादी और भविष्य

मेरे पिताजी ने अपने बच्चों के भविष्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने मेरी बहन किरण की शादी करण कुमार के साथ बड़े प्यार और सम्मान से करवाई। उसके बाद मेरी शादी भी प्रियंका के साथ करवाई। उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया।

वह दिन जो हमेशा याद रहेगा

20 नवंबर 2025, सुबह 5:15 बजे—यह वह समय है जिसे हमारा परिवार कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मेरे पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह हमारे जीवन का सबसे दुखद दिन था।

आज भी ज़िंदा है उनकी याद

आज हमारे पास सब कुछ है—जमीन, घर, परिवार, सम्मान—लेकिन मेरे पिताजी नहीं हैं। आज भी जब हम खेतों में जाते हैं, तो उनकी याद आती है। हर फसल में उनकी मेहनत दिखाई देती है। उनकी बातें, उनकी सीख, उनका प्यार—सब कुछ हमारे दिलों में जिंदा है।

एक नई सोचः शिक्षा और आगे बढ़ने की प्रेरणा

हमने कभी नहीं सोचा था कि हम खेती और मजदूरी से आगे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। आज मैं राहुल हिंदुस्तानी एक पत्रकार हूँ और अपना खुद का अखबार चला रहा हूँ। यह मेरे पिताजी के विश्वास और मेहनत का ही परिणाम है।

किसान का जीवनः हर दिन एक संघर्ष

किसान का जीवन बाहर से जितना सरल लगता है, अंदर से उतना ही कठिन होता है। मौसम की मार, फसल का जोखिम, बाजार की अनिश्चितता—हर दिन एक नई चुनौती होती है। मेरे पिताजी ने हर चुनौती का सामना किया और कभी हार नहीं मानी।

एक किसान की असली विरासत

मेरे पिताजी किरसन खिचड़ ने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी, उन्होंने हमें जीने का तरीका दिया।

उन्होंने हमें सिखाया—

- मेहनत से कभी पीछे मत हटो
- धैर्य रखो
- परिवार को सबसे ऊपर रखो

मेरे दादाजी राजाराम खीचड़ और दादी जी द्वारा दी गई एक एकड़ जमीन आज साढ़े छः एकड़ बन चुकी है—यह सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे संघर्ष की जीत है।

एक प्रेरणा, जो हमेशा जिंदा रहेगी

मेरी माता बरसी देवी ने हर मुश्किल में परिवार को संभाला। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ हर संघर्ष को झेला। आज हमारा परिवार जो भी है, वह इन दोनों की मेहनत और त्याग का परिणाम है। मेरे पिताजी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनकी मेहनत और उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी।

"वो चले गए, लेकिन उनका संघर्ष हमें आगे बढ़ने की ताकत देता रहेगा। एक किसान कभी मरता नहीं—वह अपनी मेहनत और अपनी फसल में हमेशा जिंदा रहता है।"

लेखक : राहुल हिंदुस्तानी

किसान की टूटी उम्मीदें

हरियाणा के खेतों में बर्बादी की मार

हरियाणा, जिसे भारत का 'गेहूं का कटोरा' और 'दूध-दही का खाणा' कहा जाता है, आज एक गहरे मानवीय संकट के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ की मिट्टी की सोंधी खुशबू अब किसानों के आंसुओं की नमकीन गंध में तब्दील हो रही है। जब हम दिल्ली की चमक-धमक वाली गलियों में बैठकर रोटी का निवाला तोड़ते हैं, तो शायद ही हमारा ध्यान उस हाथ की ओर जाता है जो पसीने से तर-बतर होकर जेठ की दुपहरी और पूस की रातों में मिट्टी से सोना उपजाता है। लेकिन आज वही हाथ खाली हैं, और उन हाथों की लकीरों में सिर्फ भविष्य की अनिश्चितता और कर्ज का बोझ दर्ज है।

मौसम की बेरुखीः जब कुदरत ही दुश्मन बन जाए

इस साल हरियाणा के किसानों ने अपनी पूरी जमा-पूंजी और अपनी रातों की नींद गेहूं और सरसों की फसल के नाम कर दी थी। मार्च की शुरुआत तक खेतों में लहराती पीली सरसों और सुनहरी गेहूं की बालियां एक समृद्ध भविष्य का संकेत दे रही थीं। लेकिन प्रकृति का चक्र ऐसा घूमा कि सब कुछ मटियामेट हो गया।

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने केवल फसलों को नहीं गिराया, बल्कि किसान की कमर तोड़ दी है। झज्जर, रोहतक, हिसार और भिवानी जैसे जिलों में ओलों का आकार इतना बड़ा था कि उन्होंने खड़ी फसल को जमीन पर बिछा दिया। वैज्ञानिक भाषा में इसे 'लॉजिंग' कहते हैं, लेकिन किसान की भाषा में यह उसकी 'चिता' के समान है। जब गेहूं की बाली पकने के करीब होती है और उस पर पानी या ओले गिरते हैं, तो दाना काला पड़ जाता है और उसका वजन घट जाता है। इससे न केवल पैदावार कम होती है, बल्कि मंडी में उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।

कपास का घावा अभी भरा भी नहीं था...

एक पुरानी कहावत है— 'गरीबी में आटा गीला'। हरियाणा के किसान पर यह सटीक बैठती है। मौजूदा रबी सीजन की तबाही से पहले, खरीफ के सीजन में कपास (रुई) के उत्पादकों को भारी चपत लगी थी। भारी जलभराव और गुलाबी सुंडी के हमले ने कपास की बेल्ट को बर्बाद कर दिया था।किसान ने सोचा था कि कपास में हुए घाव को वह गेहूं और सरसों की मरहम से भर लेगा। उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, खाद और बीज के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज स्थिति यह है कि किसान न तो पिछला कर्ज उतारने की स्थिति में है और न ही अगली फसल (मूंग या चारे) की बिजाई के लिए उसके पास बीज खरीदने के पैसे बचे हैं।

कर्ज का चक्रव्यूहः किसान और साहूकार

भारत में किसान पैदा कर्ज में होता है, कर्ज में ही जीता है और अक्सर अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में कर्ज ही देकर जाता है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग व्यवस्था के बावजूद आज भी 'आढ़ती' और स्थानीय साहूकार का दबदबा है। फसल खराब होते ही बैंक का नोटिस और आढ़ती का तगादा किसान के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है।

आर्थिक तंगी केवल रोटी के संकट तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-ब्याह रुक गए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही है और इलाज के अभाव में बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं। जब एक एकड़ की फसल बर्बाद होती है, तो उसका असर केवल उस किसान पर नहीं, बल्कि उस गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। गांव का छोटा दुकानदार, मोची और दिहाड़ी मजदूर—सब इस बर्बादी की चपेट में आते हैं।

फसल बीमा योजनाः राहत या आफत?

सरकार की 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' कागजों पर एक क्रांतिकारी कदम लगती है, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। 'राजधानी चौपाल' की टीम ने जब प्रभावित गांवों का दौरा किया, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईः

- **सर्वे में देरीः** फसल खराब होने के 72 घंटों के भीतर सूचना देनी होती है, लेकिन कई बार पोर्टल काम नहीं करता या किसान तकनीक से वाकिफ नहीं होता।
- **बीमा कंपनियों का अड़ियल रवैयाः** बीमा कंपनियां अक्सर व्यक्तिगत नुक़सान की जगह पूरे ब्लॉक को इकाई मानती हैं। अगर एक किसान का पूरा खेत बर्बाद हो गया है लेकिन पड़ोस का खेत बच गया है, तो उसे मुआवजा मिलने में भारी परेशानी होती है।
- **मुआवजे की राशिः** कई बार प्रीमियम के रूप में कटी राशि से भी कम मुआवजा किसान के खाते में आता है, जो उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

सरकारी तंत्र और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

हर आपदा के बाद नेताओं का दौर शुरू होता है। सफेद कुर्ते-पाजामे में नेताजी खेतों में जाते हैं, कुछ फोटो खिंचवाते हैं और 'गिरदावरी' के आदेश देकर चले जाते हैं। लेकिन यह गिरदावरी की प्रक्रिया इतनी धीमी और भ्रष्टाचार से लिपटी होती है कि राहत राशि पहुंचने तक किसान का धैर्य टूट चुका होता है। सरकार को चाहिए कि वह तकनीक का इस्तेमाल करे। ड्रोन्स के जरिए तत्काल सर्वे किया जाना चाहिए और मुआवजा सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, बिजली के बिलों और कृषि ऋणों की किश्तों को कम से कम एक साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक प्रभावः टूटता आत्मबल

फसल की बर्बादी का सबसे डरावना पहलू है—किसान का मानसिक स्वास्थ्य। हरियाणा का किसान स्वभाव से लड़ाका और जुझारू माना जाता है, लेकिन जब साल-दर-साल उसकी मेहनत पर पानी फिरता है, तो वह भीतर से टूट जाता है। अकेलेपन और बेबसी का यह अहसास कई बार उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। हमें केवल आर्थिक पैकेज की नहीं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर काउंसलिंग और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत है।

समाज और मीडिया की भूमिका

आज का मुख्यधारा मीडिया शहर की चकाचौंध और राजनीतिक तू-तू मैं-मैं में इतना मशगूल है कि उसे खेत की सिसकियां सुनाई नहीं देतीं। कृषि अब प्राइम टाइम की बहस का हिस्सा नहीं रही। 'राजधानी चौपाल' का मानना है कि जब तक देश का बुद्धिजीवी वर्ग और शहर में रहने वाला मध्यम वर्ग किसान की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझेगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमें यह याद रखना होगा कि यदि किसान खेत छोड़ देगा, तो सोने और चांदी के सिक्कों से पेट नहीं भरा जा सकेगा।

भविष्य की राहः समाधान की तलाश

समस्या केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है। हमें दीर्घकालिक समाधानों की ओर बढ़ना होगाः

- **जलवायु अनुकूल कृषिः** वैज्ञानिकों को ऐसी किस्मों पर काम करना होगा जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश को झेल सकें।
- **ड्रेनेज सिस्टमः** हरियाणा के कई जिलों में जलभराव की समस्या पुरानी है, इसके लिए जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था अनिवार्य है।
- **विकल्पः** किसान को केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय बागवानी और पशुपालन के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना होगा।

जब किसान बचेगा, तभी देश बचेगा

हरियाणा के खेतों से उठ रही यह पुकार केवल मदद की गुहार नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के खिलाफ एक चेतावनी है। किसान इस देश की रीढ़ है, और यदि रीढ़ टूट गई, तो राष्ट्र खड़ा नहीं रह पाएगा। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां खेती को घाटे का सौदा समझकर न छोड़ें।

किसान के माथे की लकीरें ही देश की प्रगति का पैमाना होनी चाहिए। आज समय है कि हम कागजी घोषणाओं से बाहर निकलकर ज़मीन पर उतरें और उस अन्नदाता का हाथ थामें जिसने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया।

लेखक : राहुल हिंदुस्तानी

ईरान जंग में ट्रम्प अपने 5 मकसद से कितने दूर...

1. मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री खत्म करना | 2. ईरान की नौसेना को खत्म करना | 3. ईरान समर्थित मिलिशिया को कमजोर करना | 4. ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना | 5. खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन

वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने 8 मिनट का वीडियो जारी करके जंग के टारगेट बताए। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अमेरिकी लोगों की रक्षा करना और ईरान से आने वाले खतरों को खत्म करना है। अब ट्रम्प के बताए टारगेट्स के मुताबिक समझते हैं कि अमेरिका को जंग में अब तक कितनी कामयाबी मिली है। उसे क्या हासिल हुआ है और क्या अब भी अधूरा है।

1. मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री खत्म करना

अमेरिका और इजराइल का अहम मकसद था कि ईरान की मिसाइल ताकत को कमजोर कर दिया जाए, ताकि वह दूर तक हमला न कर सके। इसके लिए दोनों देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने (लॉन्चर), मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिसाइल स्टोर करने के गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले किए।

इन हमलों से ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी नुकसान हुआ है। कई लॉन्चर और फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं। इससे उसकी नई मिसाइल बनाने की रफ्तार धीमी पड़ी है। लेकिन अभी भी ईरान के पास काफी मिसाइलें बची हुई हैं और वह हमले कर रहा है।

ईरान ने अपनी मिसाइलें अलग-अलग जगहों पर छिपाकर रखी हैं। कई ठिकाने जमीन के नीचे (अंडरग्राउंड) हैं, जिन्हें पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल है। कुछ मोबाइल लॉन्चर होते हैं, जिन्हें जल्दी-जल्दी जगह बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान अब सिर्फ मिसाइलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ड्रोन (मानवरहित विमान) का भी इस्तेमाल कर रहा है।

2. ईरान की नौसेना को खत्म करना

अमेरिका और इजराइल का टारगेट था कि ईरान की नौसेना को कमजोर या लगभग खत्म कर दिया जाए, ताकि वह समुद्र के रास्ते कोई बड़ा हमला या बाधा न डाल सके। इसके लिए युद्धपोत, पनडुब्बियां, नौसैनिक ठिकाने और बंदरगाह और हथियार और मिसाइल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया गया। मार्च की शुरुआत में अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉरपीडो दागकर श्रीलंका के पास मौजूद ईरानी वॉरशिप IRIS डेना को डुबो दिया। इस जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 80 लोगों की मौत हुई।

यह हमला इसलिए अहम था क्योंकि यह जहाज लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम था और हाल ही में भारत के साथ एक नौसैनिक अभ्यास में भी शामिल हुआ था। इन हमलों से ईरान के कई बड़े जहाज और संसाधन नष्ट हो गए। समुद्र में उसकी ताकत पहले से कमजोर हो गई। लंबी दूरी पर ऑपरेशन करने की क्षमता घट गई। हालांकि वह अब भी समुद्र में खतरा पैदा करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटी-छोटी तेज नावें (स्पीड बोट्स) हैं, जिनका इस्तेमाल वह अब भी कर सकता है। वह समुद्र में बारूदी सुरंग (माइन) बिछाने जैसी रणनीति अपना सकता है जो होर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्तों में छोटी ताकत भी बड़ा असर डाल सकती है।

3. ईरान समर्थित मिलिशिया को कमजोर करना

अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि ईरान जिन हथियारबंद ग्रुप्स को समर्थन देता है, उन्हें कमजोर कर दिया जाए। ये ग्रुप्स अलग-अलग देशों में ईरान के लिए काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमले भी करते हैं। इसलिए इन्हें 'प्रॉक्सी' ताकत कहा जाता है। जंग के दौरान इन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल ने खास तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। कई कमांडरों और लड़ाकों को मार गिराया। इससे इनकी ताकत कमजोर हुई, लेकिन उनका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

अमेरिका के लिए असल चुनौती यह है कि ये मिलिशिया किसी एक देश या एक जगह तक सीमित नहीं हैं। इराक, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों के अलग-अलग इलाकों में इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। इनके पास स्थानीय सपोर्ट भी होता है और अपनी अलग व्यवस्था भी होती है। ऊपर से ईरान इनकी मदद करता रहता है, जिससे ये जल्दी संभल जाते हैं। इसी वजह से, हमलों के बावजूद ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इराक में अब भी कुछ गुट अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। हिज्बुल्लाह पर लगातार हमले हुए हैं, लेकिन वह अब भी एक मजबूत ताकत बना हुआ है और पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

4. ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना

अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद यह था कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार न बना सके। ट्रम्प बार-बार कह चुके हैं कि ईरान के पास कभी परमाणु बम नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने पिछले साल ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। फिर भी अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कुछ समृद्ध यूरेनियम अब भी मौजूद है।

यह यूरेनियम जमीन के नीचे गहरी सुरंगों या बंकर जैसे ठिकानों में छिपा हो सकता है, जहां तक हवाई हमलों का असर पूरी तरह नहीं होता। अगर इन्हें पूरी तरह नष्ट करना हो, तो जमीन पर सेना भेजनी पड़ सकती है, जो बेहद जोखिम भरा कदम होगा और जंग को और बड़ा बना सकता है।

5. खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन

ट्रम्प ने ईरान की जनता से सरकार के खिलाफ उठने की अपील भी की थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ है। हालांकि ट्रम्प का दावा है कि उन्होंने रेजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े अधिकारी मारे गए। लेकिन जमीन पर अलग स्थिति दिखाई देती है। अब नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई बने हैं, जो सख्त रुख वाले माने जाते हैं और सेना के ताकतवर हिस्से के करीब हैं। कुल मिलाकर, ईरान की सरकार अब भी पहले जैसी ही है।

ईरान की सरकार अब भी धार्मिक और कड़े नियंत्रण वाली है। अमेरिका के खिलाफ उसका रुख भी पहले जैसा ही है।

अमेरिका-इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने तेल अवीव में कई मिसाइलें दागीं।

लेबनान की राजधानी बेरुत में मंगलवार को इजराइली एयरस्ट्राइक में एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई।

अमेरिका ने इस जंग में ईरान के खिलाफ 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है।

साल 2024 में यमन की राजधानी सना में मौजूद हूती लड़ाके। ईरान के समर्थन वाले ये क्षेत्रीय मिलिशिया ग्रुप अब भी सक्रिय हैं।

फार्मा इंडस्ट्री पर युद्ध का असर, शुगर-बीपी, बुखार सहित इन्फेक्शन की दवाएं महंगी :रॉ मटेरियल में 30% से 50% की बढ़ोतरी; पैरासिटामोल-एजिथ्रोमाइसिन के रेट बढ़े

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई बाधित होने और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्यप्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री में शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री में लगने वाले रॉ मटेरियल के रेट में 30% से लेकर 50% तक की बढ़ोत्तरी हुई है। इन बढ़े हुए रेट में भी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे फार्मा यूनिट्स में काम बंद होने की नौबत आ गई है। एमपी की 300 फार्मा यूनिट्स में अब तीन शिफ्ट की जगह सिर्फ एक ही शिफ्ट में दवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। नजीता यह है कि रोजमर्रा में काम आने वाली पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, शुगर और बीपी की दवाएं महंगी हो गई हैं।

फार्मा इंडस्ट्री में दवाओं के प्रोडक्शन में ये समस्याएं : इंडियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन (IDMP) मप्र के सचिव डॉ. अनिल सबरवाल ने बताया कि ड्रग्स में रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण प्रोडक्शन रेट बड़ाना मजबूरी हो गया है। सरकार का डीपीसीओ यानी ड्रग एंटरप्राइजेज कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने एक प्राइज दे रखा है कि आप किसी चीज को तय रेट से ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते हैं। अब ओवरहेड खर्चें बढ़ गए हैं। 15 रुपए में 10 गोली का प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसे में सरकार 20 से 25% रेट बढ़ाने का रिलेक्शन देती है, जो पहले ही दे चुकी है। फार्मा इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट तनाव के कारण रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। सप्लाई चेन बाधित है, लागत में वृद्धि हो रही है और इंजेक्टेबल दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक गैस की भी कुछ स्थानों पर कमी देखी जा रही है।

पेट्रोकेमिकल से बनने वाले रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन मुश्किल

फार्मा इंडस्ट्री के सबरवाल ने बताया कि पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री के बाद किसी पर आता है तो वह फॉर्मा इंडस्ट्री है। पेट्रोकेमिकल से प्रोपलीन ग्लाइकोल, पीजी 400, पीजी 6000, पीजी 5000, एसीटोन, एमडीसी, आईसोप्रोपाइल पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल से बने रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट के बिना बनी दवाएं सांस भी नहीं ले सकती हैं। इन सभी का उपयोग दवाओं को साफ करने, फिनिश करने और पालिशिंग के लिए किया जाता है। इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए इन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है।

रेट बढ़ाना दवा कंपनियों की मजबूरी : ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल ने बताया कि एमपी की जो फार्मा इंडस्ट्री की दवाईयां सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्री में सप्लाई की जाती है। अभी रॉ मटेरियल जैसे एपीआई, साल्वेंट और एल्यूमिनियम की शॉर्टेज चल रही है। दवा कंपनियों ने इस समस्यों के बाद अपने रेट बढ़ाए हैं। जहां तक फार्मा इंडस्ट्री के शट-डॉउन की बात है तो जब तक रॉ मटेरियल, एपीआई और साल्वेंट नहीं मिलेगा तो शट-डाउन तो करना ही पड़ेगा। हांलाकि अभी तक आम आदमी पर इसका असर देखने को नहीं आया है। सरकार ने वैसे 6.5 प्रतिशत से ज्यादा का प्राइस हाइक कर दिया है जिसे हर साल किया जाता है।

चीन से आने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकी : फार्मा इंडस्ट्री में दवाओं के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल चीन से आता है। वर्तमान में चीन से आने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई चैन पूरी तरह से टूट गई है। पीथमपुर एसोसिएशन के कोठारी ने बताया कि चीन से आने वाले रॉ मटेरियल जैसे डाइक्लोफेनेक, एमाक्सी, एजिथ्रोमाइसिन, पैरा-एमिनोफेनोल एम्पीसिलिन, पेनिसिलिन सहित अन्य ड्रग साल्वेंट की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है।

एम्पुल को लेकर समस्या बढ़ेगी : फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में एम्पुल यानी कांच की बोटल जिसमें इंजेक्शन लगाने की दवाई पैक की जाती है, उसको लेकर समस्या बढ़ेगी। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को एलपीजी गैस की सप्लाई सुचारू नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है। इंजेक्शन बनाने के लिए जो लॉकिंग की जाती है वह एलपीजी से ही हो पाती है। पीएनजी से लॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। लॉकिंग के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेंकड्स के अंदर ग्लास को मेल्ट करना होता है। पीएनजी में इतना प्रेशर या हीट नहीं होती है जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेंकड्स के अंदर ग्लास को मेल्ट कर लॉकिंग की जा सकें। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी भी तीन शिफ्ट की जगह एक शिफ्ट पर ही काम कर रही है।

आंतों को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। दिमाग की तरह ही आंतें पूरे शरीर के संतुलन को बनाए रखती हैं। सेहत को लेकर आंतों की अनदेखी पेट ही नहीं, दिल और दिमाग के रोगों का खतरा भी बढ़ाती है। खानपान और जीवनशैली में सुधार जरूरी है, बता रहे हैं...

आंतों की अनदेखी सेहत के लिए अच्छी नहीं...

हमारी आंतें शरीर के लिए जरूरी खरबों सूक्ष्मजीवों का घर हैं। हमारी रोगों से लड़ने की 80 से 90% क्षमता आंतों की सेहत से जुड़ी है। आंतों का हमारे इम्यून सिस्टम, मानसिक संतुलन, पाचन क्रिया और दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम से सीधा जुड़ाव है। अगर आंतें स्वस्थ हैं, तो तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। आंतों की गड़बड़ी के कारण पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। साथ ही मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसे गैर-संचारी रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास मानी जाती है। एआईआईएमएस और आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी और सूजन के मरीजों की संख्या में बीते 5 सालों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पहले ये समस्याएं ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद दिखती थीं, अब युवा और बच्चों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं।

बढ़ जाता है रोगों का खतरा

पेट साफ रहना ही आंतों की सेहत नहीं है। हमारी आंतों में रहने वाले सूक्ष्मजीव पूरे पाचन तंत्र को संतुलित रखने का काम करते हैं। ये सूक्ष्मजीव भोजन को तोड़ते हैं, पोषक तत्व अवशोषित करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करते हैं। खाना पचाने में मदद के अलावा सूक्ष्म जीव हमारे मूड और नींद पर भी प्रभाव डालते हैं। आंतों की गड़बड़ी से जुड़े प्रत्यक्ष रोगों में सबसे सामान्य है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके लक्षण पेट दर्द, कब्ज, दस्त और पेट में सूजन के रूप में प्रकट होते हैं। इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज और क्रोहन डिजीज भी इसी श्रेणी में आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, आंतों के असंतुलन से मानसिक विकार, मधुमेह, हृदय रोग, त्वचा संबंधी समस्याएं और प्रतिरक्षा में कमी जैसी स्थितियां विकसित हो सकती हैं। इसी तरह एच. पाइलोरी संक्रमण है, जिसके लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। पर, यह पेट के कैंसर का कारण बन सकता है।

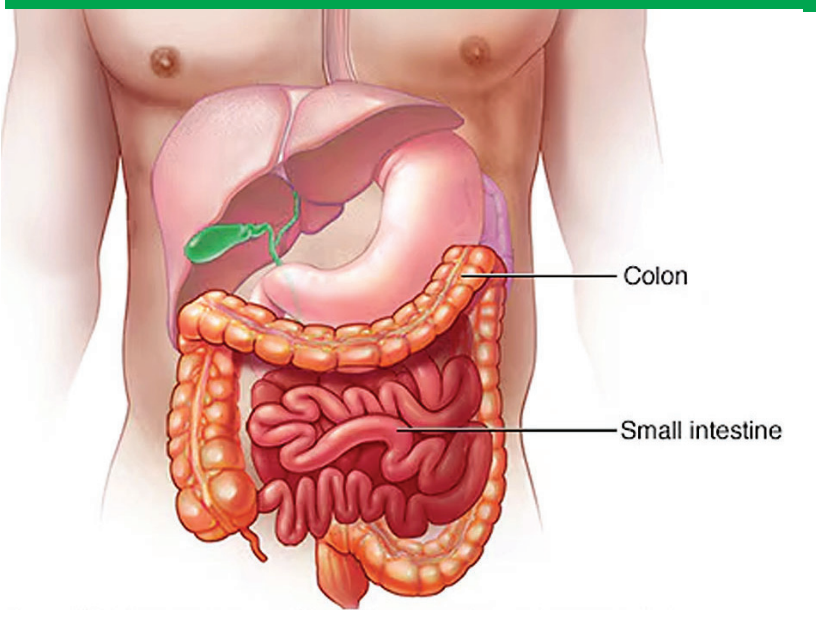

तनाव का पड़ता है बुरा असर

हमारा दिमाग और आंतें एक-दूसरे से गट-ब्रेन एक्सिस नाम के नेटवर्क के जरिये जुड़ी होती हैं। दोनों का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। मानसिक दबाव गट माइक्रोबायोम की विविधता को 40 प्रतिशत तक घटा सकता है। गट-ब्रेन एक्सिस पर हुए रिसर्च में सामने आया है कि 90% सेरोटोनिन आंतों से उत्पन्न होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो दिमाग से निकलने वाले हार्मोन आंतों की गति, पाचन और बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक लगभग 77% लोग तनाव के कारण पाचन समस्याओं से जूझते हैं। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। यही नहीं, गट हेल्थ से बच्चों की इम्युनिटी, व्यवहार और सीखने की क्षमता भी जुड़ी होती है।

आंतों के लिए अच्छी पंचकर्म थेरेपी

आयुर्वेद में आंतों को अग्नि यानी पाचन शक्ति से जोड़ा गया था। बदलती जीवनशैली, नियमित बाहर का खाना, धूम्रपान, अधिक एंटीबायोटिक दवाएं खाना, प्रोसेस्ड फूड, फाइबर की कमी, तनाव की अधिकता और नींद की कमी आतों की इस शक्ति को कम कर देते हैं। आयुर्वेद में आंतों की सेहत पर पंचकर्म थेरेपी प्रभावी पाई गई है। इसके तहत कुछ विशेष विधियों विरेचन, बस्ती (औषधीय एनीमा) आदि से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, दिल्ली के अध्ययन में पंचकर्म की विरेचन थेरेपी से आंतों के हानिकारक बैक्टीरिया ई. कोली की संख्या कम होने और आंतों में सूक्ष्मजीवों का बेहतर संतुलन देखने को मिला।

एक अन्य अध्ययन में आठ हफ्ते तक योग और पंचकर्म साथ करने से आईबीएस मरीजों के लक्षणों में कमी देखी गई। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि आयुर्वेदिक जीवनशैली और पद्धति की मदद से आईबीएस से जुड़े पेट दर्द और मल त्याग से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अलग-अलग प्रकृति (वात, पित्त, कफ) वाले लोगों की आंत में सूक्ष्मजीवों का अंतर होता है, ऐसे में भविष्य में व्यक्तिगत उपचार का रास्ता खुल सकता है।

लीकी गट सिंड्रोम, एक नई चुनौती

आंतों की सेहत पर बढ़ते शोध के बीच लीकी गट सिंड्रोम को एक नई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें आंतों की परत कमजोर होकर छोटे-छोटे छिद्र बना लेती है, जिससे बैक्टीरिया, विषैले तत्व व अधपचा भोजन सीधे खून तक पहुंच सकते हैं। यह स्थिति पाचन समस्याओं के साथ-साथ आंतों में सूजन, एलर्जी और ऑटोइम्यून रोगों को भी बढ़ावा दे सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, लीकी गट सिंड्रोम अभी तक मुख्यधारा के मेडिकल साइंस में एक औपचारिक डायग्नोसिस के रूप में भी पूरी तरह मान्यता प्राप्त नहीं है, इसका कोई एक खास टेस्ट नहीं है। कुछ टेस्ट जरूर आंतों की परत की स्थिति और उसमें सूजन का संकेत देते हैं जैसे- लैक्ट्यूलोस-मेनिटोल टेस्ट या इन्टेस्टिनल परिमएबिलिटी टेस्ट। इनसे आंत की परत की मजबूती का पता चलता है। खून व मल में प्रोटीन के स्तर को भी मापा जाता है। इसी तरह कॉम्प्रिहेन्सिव स्टूल एनालिसिस से बैक्टीरिया संतुलन, यीस्ट, बिना पचे कण और सूजन का संकेत देने वाले मार्कर्स का पता चलता है। फूड एलर्जी टेस्ट, सी-रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर व साइटोकिंस की जांच भी की जा सकती है।

आंतों की गड़बड़ी के लक्षण

- पेट में सूजन, गैस, बार-बार पेट दर्द, दस्त या कब्ज, पेट फूलना, मल त्याग में कठिनाई रहना।
- पर्याप्त आराम के बाद भी लगातार थकान।
- अकारण त्वचा का खुरदरा होना, दरारें या एलर्जी होना। अचानक मूड में उतार-चढ़ाव, बेचैनी या उदासी जैसा महसूस होना।

डॉक्टर से मिलें

- मल त्यागने की आदत में बदलाव आना। लंबे समय तक डायरिया या कब्ज रहना।
- मल में रक्त आना। लगातार पेट में मरोड़, गैस व दर्द रहना
- अचानक तेजी से वजन कम होना
- ब्रश के बाद भी मुंह से तेज दुर्गंध आना।
- पेट साफ न रहना। भूख में कमी।
- कुछ भी खाने के बाद शौच जाना।
- रात में पेट में दर्द रहना।

इन बातों को भी जानें

- **आंत और त्वचा का संबंध:** एक अध्ययन में 60% मुहांसे व एक्जिमा के मरीजों की आंतों में सूक्ष्मजीवों के संतुलन में गड़बड़ी देखने को मिली।
- **साइलेंट गट डिसऑर्डर:** बिना किसी लक्षण के शरीर में धीरे-धीरे पोषण और विटामिन बी-12 की कमी आने लगती है। इस कारण थकान रहती है।

कैसे रखें आंतें स्वस्थ

स्वस्थ जीवनशैली, मोटापे पर नियंत्रण, संतुलित भोजन, पर्याप्त फाइबर, तनाव की कमी और नियमित व्यायाम आंतों की सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। ज्यादातर पाचन संबंधी समस्याएं दवाओं और जीवनशैली सुधार से ठीक हो जाती हैं। अगर मरीज लगातार दस्त/कब्ज, बार-बार खून आने, लंबे समय तक पेट दर्द, वजन कम होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करता है, तो सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। कैंसर जैसी बीमारियां इसी लापरवाही से देर से पकड़ में आती हैं। कोलन कैंसर का परिवार में इतिहास होने पर नियमित जांच करवाते रहें।

लू के थपेड़ों के बीच थाली की सुरक्षा

लू के बीच कैसे रखें भोजन को ताजा? फ्रिज से लेकर चूल्हे तक बरतें ये सावधानी

हरियाणा और उत्तर भारत में सूरज की तपिश अब अपने चरम पर है। पारा 40 डिग्री के पार जाते ही न केवल इंसान बेहाल होता है, बल्कि हमारी रसोई में रखा भोजन भी तेजी से दम तोड़ने लगता है। गर्मियों में खाने-पीने की चीजें जितनी जल्दी खराब होती हैं, उतनी ही तेजी से वे फूड पॉइजनिंग, डायरिया और पेट के रोगों का कारण बनती हैं।

अक्सर हम छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये गलतियां अस्पताल के चक्कर लगवा सकती हैं। आज 'राजधानी चौपाल' के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि कैसे आप इस भीषण गर्मी में अपने भोजन को अमृत बनाए रख सकते हैं और उसे जहर बनने से रोक सकते हैं।

गर्मियों में भोजन के दुश्मन: बैक्टीरिया और ऑक्सीडेशन

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गर्मी में खाना आखिर खराब क्यों होता है? विज्ञान कहता है कि जब तापमान बढ़ता है, तो सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया) बिजली की रफ्तार से बढ़ते हैं। 5°C से 60°C के बीच का तापमान 'डेंजर ज़ोन' कहलाता है, जहाँ बैक्टीरिया हर 20 मिनट में दोगुने हो जाते हैं। इसके अलावा, गर्मी में खाने में मौजूद वसा (FATS) ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है, जिससे तेल वाली चीजों में दुर्गंध आने लगती है। प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे दूध, दाल और मीट इस मौसम में सबसे संवेदनशील होते हैं क्योंकि उच्च तापमान उनके रासायनिक ढांचे को तोड़ देता है।

फूड स्टोरेज के स्वर्ण नियम: सुरक्षा की पहली सीढ़ी

गर्मियों में भोजन को सुरक्षित रखने का पहला नियम है—'तापमान नियंत्रण'। फ्रिज का तापमान हमेशा 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच और फ्रीजर का -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा नियम है 'एयरटाइट स्टोरेज'। हवा में मौजूद नमी फंगस और यीस्ट को न्यौता देती है, इसलिए पके हुए भोजन को हमेशा ढक्कन बंद कंटेनरों में ही रखें। तीसरा नियम है 'क्रॉस-कंटैमिनेशन' से बचाव। कच्चे मांस और सब्जियों को पके हुए भोजन से हमेशा अलग रखना चाहिए ताकि एक के बैक्टीरिया दूसरे में न जाएं।

वह 10 गलतियां : जो भोजन को बना देती हैं बीमार

हम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जो खाने को जल्दी खराब करती हैं। इनमें सबसे बड़ी गलती है गर्म खाने को सीधे फ्रिज में रखना। इससे फ्रिज के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और दूसरी चीजें भी खराब होने लगती हैं। दूसरी गलती है फ्रिज को क्षमता से ज्यादा भरना। यदि फ्रिज में हवा के घूमने की जगह नहीं होगी, तो कूलिंग बराबर नहीं होगी। तीसरी गलती है फ्रिज के दरवाजे में दूध या अंडे रखना। फ्रिज का दरवाजा सबसे गर्म हिस्सा होता है, इसलिए संवेदनशील चीजें अंदर के शेल्फ में रखें। चौथी गलती सब्जियों को बिना धोए या गीला ही स्टोर करना है, जो सड़न पैदा करता है। पांचवीं बड़ी गलती पुराने और नए खाने को एक ही बर्तन में मिलाना है।

सब्जियों और फलों का प्रबंधन: ताजगी का राज

हरी पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धोकर पूरी तरह सुखा लें और फिर पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज के क्रिस्पर दराज में रखें। आलू, प्याज और लहसुन जैसे कंद वाली सब्जियों को कभी फ्रिज में न रखें, क्योंकि नमी इन्हें जल्दी सड़ा देती है; इन्हें किसी ठंडी और सूखी जगह पर खुला रखें। कटे हुए फलों को कभी भी बाहर न छोड़ें। यदि फल बच गए हैं, तो उन्हें तुरंत एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रखें और 24 घंटे के भीतर खा लें। अंगूर और बेरीज को तभी धोएं जब उन्हें खाना हो, वरना नमी के कारण वे तुरंत गल जाएंगे।

दूध और डेयरी उत्पाद: सावधानी ही सुरक्षा है

दूध इस मौसम का सबसे नाजुक उत्पाद है। इसे हमेशा उबालकर, सामान्य तापमान पर ठंडा करने के बाद ही फ्रिज में रखें। दूध के पैकेट को सीधे फ्रिज में रखने के बजाय उसे बर्तन में निकालकर इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है। दही को हमेशा ढककर रखें और निकालते समय सूखे व साफ चम्मच का प्रयोग करें। गर्मियों में पनीर को पानी में डुबोकर फ्रिज में रखने से वह ज्यादा समय तक नरम और ताजा रहता है, बशर्ते आप रोजाना उसका पानी बदलते रहें।

पका हुआ भोजन: 2 घंटे का कड़ा नियम

राजधानी चौपाल के पाठकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि पका हुआ खाना बनने के 2 घंटे के भीतर फ्रिज में पहुँच जाना चाहिए। यदि बाहर का तापमान 35-40 डिग्री है, तो यह समय सीमा घटकर केवल 1 घंटा रह जाती है।

बासी खाने को दोबारा गर्म करते समय ध्यान रखें कि उसे केवल एक बार ही गर्म करें। बार-बार गर्म करने से खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और जहर बनने का खतरा बढ़ जाता है।

मांसाहारी भोजन और अंडे: जोखिम का प्रबंधन

नॉन-वेज फूड गर्मियों में बहुत जल्दी खराब होता है। इसे फ्रिज में 1-2 दिन से ज्यादा न रखें। यदि आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो फ्रीजर का इस्तेमाल करें। अंडों को उनके ओरिजिनल कार्टन में ही रखें और फ्रिज के अंदरूनी शेल्फ में रखें, न कि दरवाजे पर। कच्चे मांस को हमेशा फ्रिज के सबसे निचले शेल्फ में रखें।

सूखे मेवे और स्नैक्स: नमी से बचाव

अक्सर लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खराब नहीं होते, लेकिन गर्मियों की नमी इन्हें घुन लगा सकती है या इनका स्वाद कड़वा कर सकती है। इन्हें कांच के एयरटाइट जार में रखें। बिस्किट और नमकीन जैसे स्नैक्स को सील बंद करके रखें। यदि इनमें नमी आ गई है, तो इन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से पहले हल्का रोस्ट कर लें या माइक्रोवेव कर लें।

सफाई और स्वच्छता: अंतिम और अनिवार्य उपाय

अंत में, फूड स्टोरेज तभी सफल है जब आपकी रसोई और फ्रिज साफ हों। हफ्ते में एक बार फ्रिज की गहरी सफाई करें। गंदे हाथों से खाना छूना या गंदे चाकू का इस्तेमाल करना बैक्टीरिया के लिए 'एक्सप्रेसवे' का काम करता है।

पनीर भुर्जी में 'सत्तू' का तड़का; स्वाद और प्रोटीन का बेजोड़ संगम

पनीर भुर्जी एक ऐसी डिश है जो हर भारतीय घर के नाश्ते या डिनर की शान होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा पनीर भुर्जी को और भी ज्यादा पौष्टिक और जायकेदार बनाया जा सकता है? 'राजधानी चौपाल' की खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं पनीर और सत्तू के 'जुगलबंदी' की। सत्तू, जिसे 'गरीबों का बादाम' कहा जाता है, जब पनीर के साथ मिलता है, तो यह एक हाई-प्रोटीन पावरहाउस बन जाता है। यह न केवल मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, बल्कि आपको लंबे समय तक ऊर्जावान भी रखता है।

क्यों खास है यह सत्तू ट्विस्ट?

पनीर अपनी कोमलता और कैल्शियम के लिए जाना जाता है, वहीं सत्तू फाइबर और आयरन का खजाना है। इन दोनों का मिश्रण पाचन को बेहतर बनाता है और भुर्जी को एक अनोखा 'अर्थी' (मिट्टी जैसा सोंधा) स्वाद देता है। अगर आप जिम जाते हैं या वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह डिश आपके लिए 'वरदान' साबित हो सकती है।

आवश्यक सामग्री (2-3 लोगों के लिए):

- **पनीर:** 250 ग्राम (हाथों से मैश किया हुआ)
- **सत्तू:** 2 बड़े चम्मच (चने का शुद्ध सत्तू)
- **सब्जियां:** 2 बारीक कटे प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 2 हरी मिर्च
- **मसाले:** अदरक-लहसुन पेस्ट (1 चम्मच), पाव भाजी मसाला (1 चम्मच), हल्दी (1/4 चम्मच), लाल मिर्च (1/2 चम्मच), नमक स्वादानुसार
- **तड़का:** जीरा, हरा धनिया, 2 चम्मच बटर या सरसों का तेल

बनाने की विधि: स्वाद का सफर

स्टेप 1: सत्तू की भुनाई (असली राज)
सबसे पहले एक छोटे पैन में बिना तेल डाले सत्तू को धीमी आंच पर करीब 2 मिनट तक भूनें। याद रखें, इसे जलाना नहीं है, बस जैसे ही सोंधी खुशबू आने लगे, इसे गैस से उतारकर अलग रख दें। यह भुना हुआ सत्तू ही भुर्जी में असली सोंधापन लाएगा।

स्टेप 2: तड़के की तैयारी
एक कड़ाही में बटर या तेल गर्म करें। इसमें जीरा चटकाएं और फिर बारीक कटे प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। जब प्याज का कच्चापन निकल जाए, तब टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं।

स्टेप 3: मसालों का मिलन
अब इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक और पाव भाजी मसाला डालें। मसालों को जलने से बचाने के लिए एक-दो चम्मच पानी का छिड़काव करें। अब वह खास सामग्री डालें—यानी भुना हुआ सत्तू। इसे मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें ताकि सत्तू मसालों का सारा फ्लेवर सोख ले।

स्टेप 4: पनीर का प्रवेश
अंत में मैश किया हुआ पनीर डालें। पनीर को सत्तू और मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। यदि भुर्जी ज्यादा सूखी लगे, तो ऊपर से आधा चम्मच बटर और डाल सकते हैं।

परोसने का तरीका: राजसी जायका

आपकी 'सत्तू-पनीर भुर्जी' तैयार है। इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस छिड़कें। इसे गरमा-गरम मसाला पाव या लच्छा पराठा के साथ परोसें।

यह डिश न केवल आपके पेट को तृप्त करेगी, बल्कि आपके शरीर को वह जरूरी पोषण भी देगी जिसकी उसे गर्मियों और भागदौड़ के बीच जरूरत है।

भारत बोला- हम अकेले जिसने होर्मुज में नाविक खोए

बैठक में 60 देश शामिल हुए, बोले- संकट का समाधान बातचीत से संभव

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हुए। बैठक में विक्रम मिसरी ने कहा कि होर्मुज संकट में अब तक सिर्फ भारत के ही नागरिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्मुज संकट में अब तक 3 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं, ये सभी विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। भारत ने सभी देशों से अपील की कि तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकालें।

इससे पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। यह रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी।

ट्रम्प बोले- ईरान पर जीत हासिल की, उनकी सेना हमारे कंट्रोल में : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिली है। साथ ही चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल-ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो गई है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका, ईरान को स्टोन एज, यानी पाषाण काल में भेज देगा। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर है।

ट्रम्प के भाषण में कोई नई बात नहीं : ट्रम्प ने 19 मिनट का भाषण दिया। इसमें कोई नया ऐलान नहीं किया। वही बातें दुहराईं जो पिछले कुछ समय से कहते रहे हैं। उन्होंने युद्ध की लागत और इसके लंबा खिंचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा कि वे इस संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने इराक (8 साल) और वियतनाम (19 साल) जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने में ही पहुंची है। उन्होंने यह भी माना कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, लेकिन कहा कि यह युद्ध जरूरी है। उन्होंने कहा, "यह आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश है।" ट्रम्प ने ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग की, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। हालांकि, एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि होर्मुज खोले बिना कोई समझौता नहीं होगा।

ऑस्ट्रिया ने अमेरिका को एयरस्पेस देने से मना किया : ऑस्ट्रिया ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनके देश की तटस्थ रहने की नीति है, इसलिए वे किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो सकते। मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसी मांग आई थी, लेकिन हर बार उसे अलग-अलग तरीके से देखा गया। ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह बैन नहीं लगाया है, लेकिन हर केस को अलग से जांचकर ही फैसला लेगा। इसी तरह स्पेन और इटली ने भी अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों और एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है।

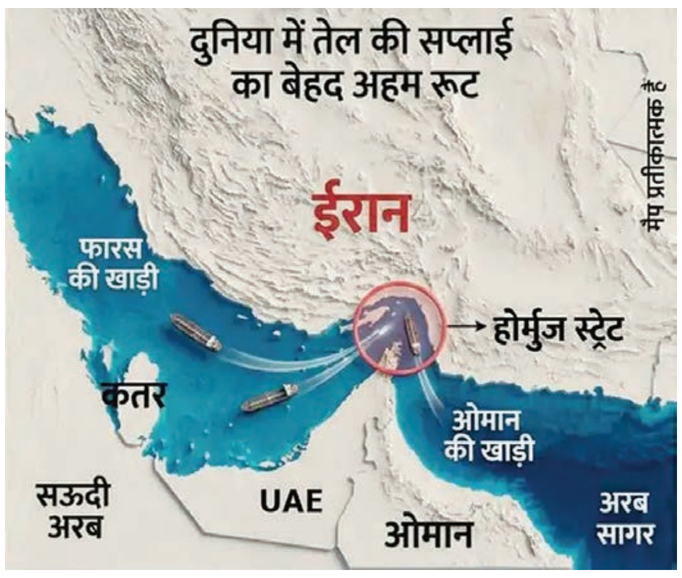

रिपोर्ट- होर्मुज संकट से अफ्रीका में खाने-पीने का संकट आ सकता है...

संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी यूनियन और अफ्रीकी विकास बैंक की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान की जंग लंबी चलती है तो इसका असर अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह संघर्ष 6 महीने से ज्यादा चलता है तो 2026 में अफ्रीका की आर्थिक विकास दर कम हो सकती है। इसके अलावा तेल, खाद और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित होने से महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों में खाने-पीने का संकट भी पैदा हो सकता है। वहीं, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में खाद और जरूरी सामान ले जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफ्रीका में खाद्य संकट आ सकता है। इस पर यूएन के साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)